A selection of clippings
on Forests & Wildlife from the Press

Himachal

GREEN PAGES

HP FOREST DEPARTMENT

Vol : 2 No. - 1

हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना

एक झलक

विश्व बैंक सहयोग की परियोजना प्रदेश के 10 जिलों के 42 विकास खण्डों की 602 पंचायतों में कार्यान्वित।

उद्देश्यः प्राकृतिक संसाधनों में हो रहे ह्रास की प्रक्रिया में कमी लाना, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी व निर्धन परिवारों की सम्पन्नता हेतु आजीविका के अतिरिक्त अवसरों में वृद्धि।

मुख्य आकर्षणः स्थानीय लोगों एवं ग्राम पंचायतों द्वारा जन सहभागिता के आधार पर नियोजन, कार्यान्वयन , संचालन तथा रख रखाव।

जलागम अधिग्रहण क्षेत्र विकास हेतु पौधरोपण, भू-संरक्षण, लधु सिचाई एवं पेयजल योजना, कृषि, बागवानी, पशुपालन, मूलभूत संसाधनों जैसे कि पैदल रास्तों और पुलों का निमार्ण आदि कार्य प्रगति पर।

महिलाओं, संसाधन विहीन और जनजातिय समुदाय के लोगों की आजीविका उपार्जन पर विशेष बल। परियोजना कार्यकाल में लगभग 20 हजार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य ।

स्वावलम्बी ग्रामीण व्यवस्था एवं सतत् विकास को सुनिश्चित करने हेतु परियोजना में समुदाय आधारित समूहों (स्वयं सहायता, लाभार्थी तथा सम-रुचि समूहों) के गठन पर विशेष बल।

क्र0सं0	परियोजना गतिविधि	ईकाई	उपलब्धियां
1.	पौधरोपण	है0	6503
2.	वर्षा जल के छत के टैंक	संख्या	4683
3.	बांध; मट्टी,पत्थर, कंकरीट	संख्या	127
4.	लधु सिंचाई योजनाएं	संख्या	219
5.	कुहल निर्माण, मुरम्मत	कि0मी0	188
6.	पैदल रास्तों का निर्माण	कि0मी0	670
7.	पैदल पुलों का निर्माण	संख्या	261
8.	पेयजल आपूर्ति	रुपये करोड.	2.86
9.	खुरली निर्माण	संख्या	12499

विभिन्न सूचनाओं से सुसज्जित, आकर्षक त्रैमासिक पत्र "मध्य हिमालय जलागम दर्पण" आरम्भ

अधिक जानकारी के लिये लॉग ऑन करें **www.hpmidhimalayan.org**

New Era 0177-2628276

Himachal
Green Pages

April-June 2010

Volume-2 No. - 1

List Of Subjects - HIMACHAL GREEN PAGES

Quarterly Compilation of Forests, Wildlife and Environment related clippings from the Press.

1. Eco Tourism..5
2. Environment & Forest related Laws (FCA,LPA)................................8
3. Events..11
4. Externally Aided Projects & Bio Carbon Project..............................12
5. Forest Conservation..13
6. Forest Fire Management..20
7. Global Warming/Climate Change...22
8. HRD. E-Samadhan/Computerisation, GIS.GPS...............................23
9. Hydro-Electric Projects, CAT PLANs and Dams etc.........................24
10. Medicinal Plants..24
11. People..28
12. Policy/Law..29
13. Wildlife Conservation/Crime/Human Animal conflict.....................32

List Of Newspapers Scanned For 'Himachal Green Pages' Quarterly

- ☞Ajit Samachar
- ☞Amar Ujala
- ☞Dainik Bhaskar
- ☞Dainik Jagran
- ☞Divya Himachal
- ☞Hindustan Times
- ☞The Indian Express
- ☞Punjab Kesri
- ☞The Tribune
- ☞The Times of India

पर्यटन के लिए एडीबी देगा 75 मिलियन डॉलर

पूर्वोत्तर सर्किट के लिए 34.32 तो पश्चिमोत्तर के लिए 40.93 मिलियन डॉलर मदद का प्रस्ताव

प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए एशियन विकास बैंक 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आर्थिक मदद देगा। बैंक ने इसे सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी।

बैंक ने हिमाचल को दो पर्यटन सर्किटों पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर में विभाजित किया है। बैंक ने पूर्वोत्तर सर्किट के लिए 34.32 मिलियन डॉलर और पश्चिमोत्तर सर्किट के लिए 40.93 मिलियन डॉलर की मदद का प्रस्ताव किया है। बैंक ने हिमाचल सरकार को ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। एशियन विकास बैंक के सहयोग से पौंग डैम को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए पूरी तैयारी है और इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

पौंग डैम साइट पर चार किलोमीटर का साइट ट्रैक, वॉच टावर्स, पार्किंग और फॉरेस्ट गेस्ट आउस और दूसरी सुविधाएं विकसित करने की योजना है इसके अतिरिक्त नगरोटा सूरियां में भी कैंपिंग साइट विकसित करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस साइट में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वाटर स्पोर्ट्स में 40 युवकों को ट्रेनिंग देकर तैयार किया है। इस संबंध में कौल सिंह ठाकुर और राकेश पठानिया ने भी प्रतिपूरक प्रश्न पूछे। बैंक की एक टीम ने 16 से 21 फरवरी के दौरान प्रदेश का दौरा किया था।

दैनिक भास्कर, 3 अप्रैल, 2010

पौंग डैम साइट के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर

सरकार की ओर से मास्टर प्लान मिलने की रही देरी

पर्यटन की दृष्टि से टूरिज्म विभाग तैयार करेगा मास्टर प्लान

रामसर साइट वेटलैंड पौंग झील की सुंदरता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संवारने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए एशियन बैंक के साथ टूरिज्म विभाग व वन्य प्राणी संरक्षण विभाग की दो चरणों की बैठक हो चुकी है।

पौंग झील में पर्यटन की अपार संभावनाओं को तलाशने आए एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य रिकार्ड शेल्टन ने प्रदेश के नंबर वन अखबार 'अमर उजाला' से बातचीत में बताया कि बैंक की ओर से पौंग झील की सुंदरता में निखार लाने के लिए प्रथम चरण में करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीते फरवरी माह की बैठक में पौंग झील पर मास्टर प्लान तैयार करने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक मास्टर प्लान बैंक के पास नहीं पहुंचा है। प्रदेश सरकार की ओर से पौंग झील पर्यटन पर मास्टर प्लान मिलते ही बैंक प्रस्तावित प्रोजेक्ट पर कार्य शुरू कर देगा। उधर, हमीरपरु स्थित वन्य प्राणी संरक्षण विभाग के डीएफओ सतीश गुप्ता का कहना है कि फरवरी महीने की बैठक में तय हुआ था कि टूरिज्म विभाग पौंग झील को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा, लेकिन उसके बाद बात कहां तक पहुंची उन्हें मालूम नहीं है।

अमर उजाला, 21 अप्रैल, 2010

धरती पर स्वर्ग है पोटरहिल

टूरिस्ट हब बन चुके स्थल में पर्यटकों को लुभाते हैं लॉग हट्स

हिल्स क्वीन के नाम से ख्याति प्राप्त शिमला में पहुंचने वाले पर्यटक यहां प्रकृति की नैसर्गिक सुंदरता का नज़ारा लेने पहुंचते हैं। यहां आने वाले सैलानियों के जहन में शुरुआत से ही मनमोहक पहाड़ियां, सुंदर पेड़ और शांत वातावरण का दृश्य रहता है और ये सब कुछ उन्हें शिमला पहुंचकर मिलता भी है। हिल्स क्वीन की सुंदरता उसके नाम से ही विख्यात है। ऐसे में यहां पोटरहिल जैसे वे रमणीक स्थल भी हैं, जो शहर से थोड़ी दूरी पर ही मौजूद हैं। पोटरहिल अंग्रेज़ी नाम और बेशक लोग यह समझते हैं कि यह अंग्रेज़ों द्वारा बसाया गया कोई स्थान है, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं। पोटरहिल जैसा स्थान खास ईको टूरिज्म के लिए स्थापित किया गया है, जिसे प्रदेश के वन महकमे ने स्वरूप दिया। घने पेड़ों से घिरा पोटरहिल शहर का ऐसा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, जहां सैलानी पहुंचते ज़रूर हैं। जंगल के रास्ते से होते हुए समरहिल से नीचे करीब चार किलोमीटर आगे पोटरहिल में स्थापित लॉग हट्स का नज़ारा देखते ही बनता है। बिलकुल पेड़ों के साथ ऐसे हट्स बने हैं, जहां गर्मियों में गर्मी का अहसास नहीं होता। शुरुआत में इन हट्स की छतों पर

घास बिछायी गई थी। लंबे बांस के डंडों से इनका निर्माण किया गया है, जिसमें रहने वालों को सभी सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। यहां रहने का अहसास बिलकुल वैसा ही है, जैसा किसी हिन्दी फिल्म में बनी मचान। मचान की तरह ऊंचे हट्स बनाए गए हैं, जिनमें अब लकड़ी के स्ट्रक्चर के साथ एल्यूमिनीयम भी लगाया है। सैलानियों को आसपास का शांत माहौल बहुत भाता है। करीब पांच साल पहले पोटरहिल का निर्माण ईको टूरिज्म की दृष्टि से किया गया। प्रदेश में ईको टूरिज्म का सबसे पहला उदाहरण पोटरहिल है। वन महकमे ने यहां बनाए गए हट्स को प्राइवेट कंपनी को सौंपा है, जो इनका रखरखाव करती है। पर्यावरण के साथ खिलवाड़ न हो इसके लिए कड़े नियम बनाए गए हैं।

दिव्य हिमाचल, 24 अप्रैल, 2010

....

जंगल में लें ट्रैकिंग का लुत्फ

वन विभाग ने ईको टूरिज्म अधिकारियों से मिलकर बनाई नई योजना

देवभूमि के शांत व ठंडे जंगलों में सैलानी अब सैर का लुत्फ उठा पाएंगे। अभी तक यहां जंगल में सैर का मज़ा लेने पर प्रतिबंध था। अब इस प्रतिबंध को खोल दिया गया है।

ईको टूरिज्म के साथ-साथ अब वन महकमा सैलानियों को जंगल में ट्रैकिंग का लुत्फ भी देगा। पहाड़ी प्रदेश के जंगलों में सैलानियों को वह सब कुछ मिलेगा, जो मैदानी क्षेत्रों में नहीं मिलता। जल्दी ही पर्यटक यहां के जंगलों में ट्रैकिंग के लिए उतरेंगे और खुद वन विभाग के गाइड उन्हें ट्रैकिंग करवाएंगे। इको टूरिज्म के कंसेप्ट के बाद विभाग ने ट्रैकिंग को शुरू करने की सोची है और बाकायदा इसके लिए प्रदेश में ट्रैकिंग स्पॉट भी चिन्हित किए हैं। शनिवार को वन विभाग के ईको टूरिज्म के अधिकारियों की इस संबंध में अहम बैठक हुई है जिसमें टूरिस्ट्स के लिए ट्रैकिंग रूट चिन्हित करने के अलावा विशेष पैकज बनाए गए हैं। जो लोग ईको टूरिज्म के लिए यहां आएंगे वे जंगल की सैर को भी जाएंगे। अभी तक इको टूरिज्म के लिए यहां आने वाले लोग एक विशेष जंगल में घूमकर वहां ठहरकर वापस जा रहे हैं लेकिन अब उन्हें जंगलों की दूर-दूर की सैर करवाई जाएगी। वन विभाग द्वारा तैयार किए गए नए पैकेज के मुताबिक केवल 15 साल से ऊपर के लोगों को ही ट्रैकिंग पर ले जाया जाएगा। वे लोग जो शारीरिक तौर से पूरी तरह स्वस्थ हों उन्हें विभाग ट्रैकिंग में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मुहैया करवाएगा। जहां-जहां जंगलों में विभाग ने टैंटिंग सुविधा उपलब्ध करवाई है, वहां सभी जगहों पर ट्रैकिंग रूट होंगे। पहले चरण में विभाग ने करीब आठ ट्रैकिंग रूट चिन्हित किए हैं। इनमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में चार रूट हैं। बता दें कि अभी तक इस पार्क में किसी को भी घूमने फिरने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा शिमला के साथ लगते शाली टिब्बा की सैर भी जंगल के रास्ते पर्यटकों को करवाई जाएगी। शाली टिब्बा के लिए विभाग ने एक दिन का पैकेज बनाया है जबकि दूरदराज के क्षेत्र चौपाल के मशहूर स्थान चूड़धार तक जाने के लिए तीन दिन का पैकेज बनाया गया है। वन विभाग मई माह से जून माह के बीच पर्यटकों को पहले चरण में ट्रैकिंग करवाएगा। विभाग के मुख्य अरण्यपाल विनीत कुमार ने बताया कि ईको टूरिज्म के साथ ट्रैकिंग को शुरू करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

दिव्य हिमाचल, 26 अप्रैल, 2010

....

Forest dept to promote eco-tourism

Encouraged by the success of eco-tourism villages, the state Forest Department has decided to organise trekking expeditions for summer holiday-makers on a large scale to help disperse tourism-related activities to interior pockets of the state. The department has identified five routes of varying duration ranging from one day to eight days.

Tourists would be taken in groups of 15 to 20 and would also be acquainted with the local flora, fauna and culture.

In all, 11 trekking expeditions for two, each for four long treks, and three for the one-day trek, would be organised starting from May 15. The trekking would conclude by the end of June.

Chief conservator of forests, eco-tourism, Harsh Mittar said local people would be involved through eco-tourism societies and would be the main beneficiaries of the programme. The ultimate objective was to train the local people so that they could organise such activities on their own. The role of the department would be that of a facilitator as had been in the case of eco-tourism villages, he added.

The single-day trek to Shali Tibba, near here, will cost Rs. 1,500, while Rs. 5,000 will be charged for the four-day trek to 12,500-ft. Churdhar.

The three long-duration routes are in and around the Great Himalayan National Park (GHNP) in Kullu. The two eight-day treks, one across the GHNP and the other in Tirthan valley, will entail an expenditure of Rs. 11,200, while the six-day trek in Sainj valley will cost Rs. 8,100.

Private parties and local

people were now coming forward to run eco-tourism villages and about a dozen such resorts would be in operation in various parts of the state during summer. They include Moti Kuna Hills near Dharampur, Barog, Barog bypass, Shoghi, Narkanda, Jalori pass, Naldehra, Narkanda and Potters Hill.

The Tribune, April 28, 2010

मैदानी पर्यटक शीघ्र करेंगे घने जंगलों का भ्रमण

ईको टूरिज्म के साथ-साथ वन विभाग द्वारा प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को वन क्षेत्र में ट्रैकिंग भी करवाने की योजना बना रहा है। इसके प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वन विभाग व ईको टूरिज्म के अधिकारियों के बीच हाल ही में हुई एक बैठक में इस सारे मामले पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया तथा जल्द ही मैदानी क्षेत्रों में आने वाले पर्यटक हिमाचल प्रदेश के घने जंगलों की सैर करेंगे।

इतना ही नहीं वनों में ट्रैकिंग के दौरान वन विभाग के गाइड पैकेज के साथ रहेंगे। इसके लिए वन विभाग द्वारा एक नया पैकेज बनाया गया है जिसमें ऐसे लोगों को ही जंगलों में ट्रैकिंग करवाई जाएगी जिनकी आयु 15 साल से अधिक हो और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। यहां आने वाले पर्यटकों को विभाग द्वारा ट्रैकिंग का सामान भी उपलब्ध करवाया जाएगा। जंगलों में जिन स्थानों पर विभाग द्वारा टैंटों की सुविधा उपलब्ध है उन स्थानों पर विभाग द्वारा विशेष ट्रैकिंग रूट बनाए गए हैं।

पंजाब केसरी, 25 मई, 2010

देहरादून के दल ने किया ईको टूरिज्म का अध्ययन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून में भारतीय वन सेवा के 42 प्रशिक्षु अफसरों का एक दल हिमाचल आया है। इसकी अगुवाई अकादमी के प्रतिनिधि राजीव शर्मा कर रहे हैं। यह दल प्रदेश के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन का अध्ययन करेगा।

वन विभाग के डीएफओ (प्रचार) एसएस कटैक ने बताया कि पहले दिन इस दल ने प्रसिद्ध शिमला वाटर कैचमेंट के देवदार वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और पोटर हिल में ईको टूरिज्म के कार्यों का अध्ययन किया।

उन्होंने कहा कि वनों और वन्य प्राणियों के प्रबंधन के अध्ययन के लिए प्रशिक्षु अफसर मनाली, धर्मशाला, कालाटोप व खजियार का भी दौरा करेंगे। शिमला में बुधवार को इस दल के साथ विभाग ने संगोष्ठी आयोजित की। इस मौके पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल विनय टंडन ने कहा कि वन हिमालय क्षेत्र के नाजुक पर्यावरण को संतुलित रखने के साथ-साथ देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी अहम भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने कहा कि वनों के संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। टंडन ने युवा प्रशिक्षुओं का आह्वान किया कि वे वनों में जाकर इनके प्रबंधनों में हो रहे बदलावों का अध्ययन करें और इस दौरे को दस्तावेजों की शक्ल जरूर दें। इस अवसर पर वन्य प्राणी के प्रधाान मुख्य अरण्यपाल एके गुलाटी, शिमला के अरण्यपाल एस. के. शर्मा समेत विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे।

दैनिक भास्कर, 10 जून 2010

त्रियूंड-खड़ापत्थर बनेगी ईको साइट

वन महकमे की कवायद शुरू लीज पर दी जाएगी भूमि

हिमाचल प्रदेश वन विभाग पांच और ईको साइट आबंटित करेगा। पांच वर्ष की अवधि के लिए इन्हें लीज पर दिया जाएगा। पिछले वर्ष विभाग द्वारा दस साइट्स को आबंटित किया था। इन साइट्स को लीज पर देने से विभाग को एक करोड़ 13 लाख रूपए की आमदन होगी। इन साइटों को आबंटित करने के लिए वन विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। इन साइटों में त्रियूंड, खड़ापत्थर, महासू, हाब्बन व शोजा शामिल हैं। पिछले वर्ष आबंटित दस ईको साइट के अच्छे नतीजे आने के बाद वन महकमे ने पांच और साइट चिन्हित की है, जिन्हें जल्द ही आबंटित किया जा रहा है। इन ईको साइट्स में पर्यटकों को ठहरने के लिए टैंट आदि लगाए जाएंगे, जिनमें खाने-पीने की भी व्यवस्था होगी। पिछले वर्ष आबंटित दस साइट्स में से जलोड़ी जोत और नारकंडा को पर्यटकों के लिए शुरू किया जा चुका है। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक देश-विदेश से आने वाले पर्यटक होटलों में ठहरने के अलावा इन साइट्स में ठहरना अधिक पसंद कर रहे हैं। इसी के चलते निगम की भी अच्छी खासी आमदन हो रही है वन विभाग के कंजरवेटर विनित कुमार ने माना की पांच और ईको साइट्स को जल्दी ही आबंटित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस के लिए क्वायद शुरू हो चुकी है। उधर, वन विभाग द्वारा जलोड़ी जोत व नारकंडा में शुरू की गई ईको साइट्स से अभी तक बीस लाख रूपए की आमदन हो गई है। वन विभाग का कहना है कि ट्राइबल टूरिज्म में

यहां पर पर्यटकों की अधिक आवाजाही होने की उम्मीद है। जुलाई से सितंबर महीने तक प्रदेश में ट्राइबल टूरिज्म काफी परवान चढ़ता है।

सोनू बंगलों को परमिशन

वन विभाग द्वारा शिमला के शोघी समीप सोनू बंगलो में बनाई गई ईको साइटस को चलाने का रास्ता साफ हो गया है। स्थानीय लोग इस साइट को लेकर काफी विरोध कर रहे थे, जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा था। लोगों ने यहां पर अवैध पेड़ कटान का आरोप भी लगाया था। वन विभाग का कहना है कि उच्च न्यायालय ने इस साइट को चलाने के लिए अनुमति दे दी है।

दिव्य हिमाचल, 30 जून, 2010

....

Environment/Forest related Laws (FCA, LPA)

हिमाचल को मिले कार्बन क्रैडिट : डॉ० कलाम

पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के लिए कहा – 'वैल्डन'

भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारतरत्न डॉ० ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में शानदार उपलब्धियों के लिए बधाई दी है। डॉ. कलाम ने आज प्रो. धूमल से दूरभाष पर बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आम लोगों की सहभागिता के लिए प्रभावी पग उठाकर इसे जनांदोलन बनाने में देश के अन्य राज्यों का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि वह वैश्विक उष्मीकरण के दृष्टिगत पर्यावरण ह्रास के बारे में चिंतित हैं जिसके परिणामस्वरूप मौसम परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में पर्यावरण में हो रहे बदलाव का वह नियमित अनुश्रवण कर रहे हैं। उन्होंने हिमाचल में पेड़ों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध, प्लॉस्टिक बैग के उपयोग पर रोक, ईको बटालियन का गठन, शिक्षा संस्थानों में ईको क्लब एवं जड़ी–बूटी एवं पौधों की किस्मों के रोपण के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए प्रदेश की प्रशंसा की। डॉ० कलाम ने हिमाचल प्रदेश की देश में कार्बन न्यूट्रीलिटी में अग्रणी होने के लिए प्रशंसा की तथा कहा कि हिमालयी पारिस्थितिकी के लिए राज्य को कार्बन क्रैडिट मिलना चाहिए।

उन्होंने राज्य द्वारा आरंभ किए गए विशेष पौधारोपण अभियान की भी प्रशंसा की। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वह अन्य राज्यों को भी परामर्श देंगे कि वे पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए हिमाचल का अनुसरण करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाल ही में कोस्टारिका गए उच्च स्तरीय दल से जानकारी प्राप्त की तथा आशा व्यक्त की कि वहां के अनुभव राज्य के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सहायक होंगे। प्रो. धूमल ने डॉ. कलाम को प्रदेश में आने का निमंत्रण भी दिया।

पंजाब केसरी, 3 अप्रैल, 2010

....

पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील

मुख्यमंत्री ने गेयटी थियेटर में किया चित्रकला कार्यशाला का शुभारंभ

पर्यावरण विरोधी गतिविधियों व कंक्रीट निर्माण पर रखी जा रही नज़र

मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिमला शहर के लोगों को पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण से विभिन्न क्षेत्रों के कलाकारों को भी इसके प्राकृतिक सौन्दर्य से अपनी कला में सृजनात्मकता लाने की प्रेरणा मिलेगी।

मुख्यमंत्री सोमवार को गेयटी थियेटर में शिमला शीर्षक से आयोजित चित्रकला कार्यशाला का शुभारंभ करने के बाद संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला ललित कला अकादमी नई दिल्ली तथा भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित की गई। धूमल ने कहा कि शिमला को सुहावने मौसम व प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्वभर में जाना जाता है तथा यह पर्यटकों का पसंदीदा स्थल भी है। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण विरोधी गतिविधियों व कंक्रीट निर्माण पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। शिमला विभिन्न चित्रकारों का प्रेरणास्रोत रहा है व उनकी कलाकृतियों में इसकी साफ झलक देखी जा सकती है। यहां अपनी कलाकृतियों संवारने के साथ–साथ कला प्रेमी प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता को भी अनुभव कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष ऐतिहासिक गेयटी थियेटर के पुनः खुलने से यहां विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों को गति मिली है और देश व विदेश के कलाकार यहां प्रस्तुतियां दे रहे हैं। सरकार गेयटी थियेटर को सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस अवसर पर धूमल ने

कलाकारों को भी सम्मानित किया। ललित कला अकादमी नई दिल्ली के सुधाकर शर्मा ने कहा कि देशभर में अकादमी की शिमला शाखा को उच्च स्तर पर आंका गया है। यहां पर गुणात्मक कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाते हैं।

दैनिक जागरण, 6 अप्रैल, 2010

....

पर्यावरण मित्र होटलों की होगी रैंकिंग

मुख्यमंत्री ने किया 'पालीथीन हटाओ पर्यावरण बचाओ' अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ

धूमल ने कहा, पर्यावरण सरंक्षण में जल्द अव्वल होगा हिमाचल

पर्यावरण मित्र होटलों की बनेगी सूची सैलानियों को दी जाएगी इनकी जानकारी

हिमाचल में अब पर्यावरण के प्रति जागरूक होटलों की रैंकिंग होगी। पर्यावरण मित्र होटलों की सूची तैयार की जाएगी और सैलानियों को इन होटलों के बारे में बताया जएगा। इसके अलावा प्रदेश में आने वाले सैलानियों को नाकों पर ही पर्यावरण सरंक्षण संबंधी पर्चे बांटे जाएंगे। उन्हें बताया जाएगा कि हिमाचल प्रवास के दौरान उन्हें किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट करना है।

वीरवार को शिमला के राज्य अतिथि गृह पीटरहाफ में 'पालीथीन हटाओ-पर्यावरण बचाओ' अभियान के दूसरे चरण के शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठा रही है और जल्द हिमाचल पर्यावरण के क्षेत्र में देशभर में अव्वल होगा।

उन्होंने कहा कि भारतीय जीवन पद्धति जल, जंगल व ज़मीन को शुरू से ही प्राथमिकता दी गई है। पर्यावरण संरक्षण हमारे संस्कारों में है, लेकिन दुख की बात है कि इसे समझा नहीं गया। यदि समूचे विश्व ने भारतीय जीवन दर्शन को आत्मसात किया होता तो आज पर्यावरण को लेकर इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कचरा इधर-उधर फेकने से उपजने वाली परेशानियों का ज़िक्र करते हुए उदाहरण दिया कि कुल्लू-मनाली जाने वाले सैलानियों द्वारा फेंके गए कचरे से 126 मैगावाट की लारजी परियोजना में अवरोध आ गया था और उसे एक दिन के लिए बंद करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि गंदगी फैलाकर फिर उसे समेटने से तो बेहतर है कि पहले ही इस बारे में जागरूकता पैदा की जाए।

गुटखा खाने वालों की आएगी शामत

समारोह में लोकनाट्य करियाला के माध्यम से कलाकारों ने पालीथीन कचरे के खतरे बताए। कलाकारों ने बताया कि गुटखे के छोटे पैकेट्स से जो कचरा फैलता है, उसे कैसे रोका जाए।

गुटखा खाने वाले हर कहीं खाली पैकेट फेंक देते हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि गुटखा खाने वालों को मौके पर ही जुर्माना दिया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थलों पर गुटखे के पैकेट फेंकने वालों को मौके पर ही जुर्माना किया जाए।

प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करो, पैसे पाओ

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी संस्था या व्यक्ति प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर स्थानीय निकासों को देगा उसे तीन रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। स्थानीय निकायों को एक रुपया हैंडलिंग चार्ज दिया जाएगा। लोक निर्माण विभाग यह पैसा देगा।

स्कूली बच्चे सीखेंगे पर्यावरण का क, ख, ग

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें यह करो और यह न करो के तहत पर्चे दिए जाएंगे। इससे स्कूली बच्चों में जागरूकता आएगी और वे पर्यावरण का महत्त्व समझ सकेंगे।

दैनिक जागरण, 23 अप्रैल, 2010

....

कशांग परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति : धूमल

अधिकारियों को जलविद्युत परियोजनाओं की औपचारिकताओं को पूरा करने का निर्देश

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एकीकृत कशांग (243 मेगावाट) जलविद्युत परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की है।

यह जानकारी शुक्रवार को मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद दी। उन्होंने कहा कि 243 मेगावाट की एकीकृत कशांग जलविद्युत परियोजना का निष्पादन हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो राज्य के विभिन्न भागों में इस तहर की कई परियोजनाओं का निष्पादन कर रही है। पर्यावरण स्वीकृति मिलने के साथ ही कार्यान्वयन प्राधिकरण परियोजना का निर्माण कार्य तीव्र गति से संचालित होगा।

राज्य में 65 मेगवाट के प्रथम चरण को वित्तपोषण के लिए एशियन विकास बैंक को प्रस्तुत किया गया था। इसके लिए 297 करोड़ रुपये स्वीकृत करवाने में सफलता मिली। 130 मेगावाट एकीकृत परियोजना के दूसरे व तीसरे चरण के निष्पादन के लिए राज्य ने एशियन विकास बैंक प्राधिकरण को वित्तीय सहायता के लिए पुन: आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार कर एशियन विकास बैंक को अतिरिक्त 453 करोड़ रुपये स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया, ताकि इसका निष्पादन सुनिश्चित बनाया जा सके। पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात शेष राशि शीघ्र स्वीकृत होगी। एशियन विकास प्राधिकरण परियोजना के प्रथम चरण के निर्माण कार्य की प्रगति से संतुष्ट है तथा उसने परियोजना के तीव्र विकास की सराहना की है। धूमल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रमुख इकाई के रूप में उभरकर आई है। निगम को कई बड़ी परियोजनाएं आबंटित करने से यह राज्य में चिन्हित जलविद्युत क्षमता के शीघ्र दोहन में महत्वपूर्ण योगदान देगी। निगम को जलविद्युत परियोजनाओं के उत्पादन में उच्च व्यवसायियों द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है, जिनका राज्य के विभिन्न भागों में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में बेहतर अनुभव रहा है।

मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राथमिकता के आधार पर जलविद्युत परियोजनाओं की औपचारिकताओं को पूरा करें, ताकि इनका निर्माण निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जलविद्युत निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हिप्र. पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड निर्धारित समयावधि में लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, ताकि क्षेत्र में विद्युत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके व चिन्हित जलविद्युत क्षमता का दोहन शीघ्र सुनिश्चित बनाया जा सके।

दैनिक जागरण, 24 अप्रैल, 2010

....

Himachal frames environment code for schools

In a bid to rope in school children and educational institutions in the sustained environment campaign, Himachal Pradesh on Monday launched a nine-point Environment Protection Code. The code makes it mandatory for teachers and students to undertake environment protection pledge in the morning prayers.

The idea is to make the future citizens conscious of the environment and also use them as ambassadors in the awareness drive for protection of the fragile Himlayan ecology and environment. The code has been prepared by the Department of Environment, Science and Technology.

The move has come at a time when other BJP ruled states are trying to push saffron agenda in the schools books and curriculums.

The suggestion for framing the code came up during a function organised to launch the second phase of the drive against use of the banned polythene begs and other plastic material last week. Chief Minister Prem Kumar Dhumal had endorsed the initiative and asked the Environment department to go ahead.

"The schools have been asked to take a pledge for keeping the state clean, green and beautiful in the real sense and not to use non-biodegradable plastic bags, and also spread this message to other citizens," reads the code.

The teachers will be required to administer pledge to the students motivating them to respect all living beings, plant, conserve and protect trees and conserve paper by doing rough work on slate or black board. Students would be motivated to conserve water at all times by ensuring that no one in the house should keep taps running during brushing, washing, shaving and bathing, conserve energy by switching off the lights and other electric appliances when not in use.

The Indian Express, May 4, 2010

....

पर्यावरण पर शिमला में होगा फिल्म फैस्टीवल

विश्व वाइल्ड लाइफ फंड और भाषा एवं संस्कृति विभाग 2 जुलाई को सी.एम.एस. वातावरण-2010 विषय पर फिल्म फैस्टीवल का आयोजन करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में पर्यावरण बदलाव, भारतीय एवं राष्ट्रीय फिल्म स्क्रीनिंग, प्रदर्शनी, ईको टिप्स, पेंटिंग प्रतियोगिता, फिल्म मेकिंग वर्कशाप के माध्यम से पर्यावरण बदलाव के कारणों का खुलासा किया जाएगा। यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में वन प्रधान मुख्य अरण्यपाल ए.के. गुलाटी व विश्व वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया की प्रदेश निदेशक वंदना थपलयाल ने बताया कि इस तरह के फैस्टीवल भारत

के 8 शहरों में आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें शिमला भी शामिल है। इसमें कुल 40 ईनाम उन फिल्मों को दिए जाएंगे जो बेहतर साबित होगी। चौथा थीम वातावरण से संबंधित रहेगा जिसमें पर्यावरण बदलाव मुख्य मुद्दा रहेगा और इस पर चर्चा भी की जाएगी। भाषा एवं संस्कृति विभाग के निदेशक डॉ. प्रेम शर्मा ने बताया कि गेयटी थियेटर में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। और अन्य मुख्य शहरों की तरह यहां भी इसे सफल अंजाम दिया जाएगा।

पंजाब केसरी, 16 जून, 2010

विश्व बैंक देगा 2200 करोड़ रूपए

क्लाइमेट चेंज डिवेलपमेंट पालिसी के तहत प्रदेश को सहायता

विश्व बैंक जुलाई माह हिमाचल को 450 मिलियन डॉलर (2200 करोड़) रूपए की वित्तीय सहायता जारी कर सकता है। इसमें 90 फीसदी सहायता राशि होगी, जबकि दस प्रतिशत ऋण की शक्ल में होगा। यह राशि क्लाइमेट चेंज डिवेलपमेंट पॉलिसी लोन के तहत जारी की जाएगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रलय ने राज्य के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जबकि वित्त मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ इकोनोमिक अफेयर्स ने स्वीकृति प्रदान करनी है। इसी सिलसिले में राज्य की अतिरिक्त मुख्य सचिव सरोजनी गंजू ठाकुर ने 14-15 जून को केन्द्रीय महकमें की स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुतिकरण दिया है। राज्य की पर्यावरण मास्टर प्लान भी जुलाई तक मुकम्मल होने की सूचना है। प्लान में शुमार सिफारिशों को विश्व बैंक की इसी वित्तीय सहायता से अमलीजामा पहनाया जाएगा। यह प्रोजेक्ट वर्ष 2015 तक चलेगा, जिसमें राज्य की सभी पंचायतों व गांवों को शामिल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार इस बारे में केन्द्रीय मंजूरी मिलते ही ऐलान कर सकती है। पर्यावरण निदेशालय का वर्ष 2007 के बाद गठन होने के बाद यह सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल होगा। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार व पर्यावरण निदेशालय इस प्रोजेक्ट पर पिछले नौ माह से कार्य करने में जुटे थे। पांच साल के इस प्रोजेक्ट में प्रदेश के कृषि बागवानी, वन, पीडब्लयूडी, पंचायती राज, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य महकमें समन्वय बिठाकर कार्य करेंगे। विश्व बैंक के विशेषज्ञ नियमित तौर पर प्रोजेक्ट की निगरानी करेंगे, जबकि पर्यावरण निदेशालय बतौर नियंत्रक व डोनर एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। सूत्रों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद पंचायत व गांवों को वायु, जमीन व जल प्रदूषण से पूरी तौर से निजात दिलाना होगा। इसके अलावा क्लाईमेट चेंज डिवेलपमेंट पॉलिसी लोन को सैद्धांतिक मंजूरी देने से पूर्व विश्व बैंक की टीमें सात बार प्रदेश के विभिन्न इलाकों का दौरा कर चुकी है।

पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा प्रशिक्षण

पंचायतों व गावों में सीवरेज व्यवस्था में सुधार, वनीकरण व जल-संरक्षण सरीखे प्रयास किए जाएंगे। इस संदर्भ में पंचायतों व गांवों के लोगों व पदाधिकारियों को क्षमता निर्माण के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा।

दिव्य हिमाचल, 22 जून, 2010

Events

नारा लेखन में रजत ने मारी बाजी

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भौंट ने वीरवार को पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस उपलक्ष्य पर छात्रों की नारा लेखन, चित्रकला, कविता पाठ, लघुनाटिका और भाषण प्रतियोगिताएं करवाई गई। नारा लेखन प्रतियोगिता में रजत ने प्रथम और अजय कुमार ने द्वितीय स्थान हासिल किया। भाषण प्रतियोगिता में सपना पहले और महिमा दूसरे स्थान पर रही। कविता पाठ में शिवाली ने बाजी मारी जबकि पूजा दूसरे स्थान पर रही। लघुनाटिका में धरा की अक्षुधरा में सूरज और साथियों ने शानदार अभिनय कर सबका मनोरंजन किया। स्कूल प्रिसींपल पीसी चौहान ने विजेता छात्रों को पुरस्कार बांटे। मंच संचालन करते हुए यशवंत शर्मा ने छात्रों को पृथ्वी दिवस की जानकारी दी। इसके अलावा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठियोग के रिंकू डोगरा ने दूसरा, कुफरी की पूजा वर्मा ने तीसरा और ढली के राजेश ने चौथा स्थान हासिल किया।

पृथ्वी दिवस का महत्त्व बताया

वन्य प्राणी प्रभाग ने डबल्यूडबल्यूएफ इंडिया के सहयोग से वीरवार को कुफरी के हिमालयन नेचर पार्क में पृथ्वी दिवस मनाया। इस अवसर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ठियोग, कुफरी और ढली के छात्रो ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत में डबल्यूडबल्यूएफ की राज्य निदेशिका वंदना थपलियाल ने छात्रों को

पृथ्वी दिवस की जानकारी दी। उन्होंने छात्रों को बताया कि पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित हो रहा है और इसे कैसे बचाया जा सकता है। वन्य प्राणी प्रभाग के अधिकारियों ने छात्रों को वन्य प्राणियों और जैव विविधता की जानकारी दी। इस मौके पर चित्रकला प्रतियोगिता भी करवाई गई जिसमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ढली की सोनिका ने पहला स्थान हासिल किया।

दैनिक भास्कर, 23 अप्रैल, 2010

....

वन महोत्सव से शुरू होगी वन विहार योजना

पूर्व सैनिक कल्याण समिति को मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

पूर्व सैनिक कल्याण समिति द्वारा शहीदों के नाम पर वन विहार बनाए जाने की योजना पर मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने भी सहमति जताई है। उन्होंने वन विहारों के निर्माण की प्रक्रिया जुलाई माह में मनाए जाने वाले वन महोत्सव के मौके से शुरू करने का आश्वासन दिया। समिति द्वारा शुरू किए इस कार्य की सराहना करते हुए प्रो. धूमल ने कहा कि इनकी स्थापना किए जाने के लिए सरकार भी समिति के साथ है व इसके लिए समिति को हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीद हुए प्रदेश के रणबांकुरों की कुर्बानी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दुश्मन देश द्वारा थोपे हर युद्ध में हिमाचली सपूतों ने अदम्य साहस का परिचय दिया है व उन्हीं कुर्बानियों के कारण देवभूमि को अब वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध में अपने प्रस्तावित दौरे से पूर्व शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ पल निकाल कर बरठीं विश्रामगृह में झंडूता व घुमारवीं विधानसभा चुनाव क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्त्ताओं व लोगों की समस्याएं सुनीं तथा शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ विधानसभा उपाध्यक्ष रिखी राम कौंडल भी मौजूद थे। इस मौके पर पूर्व सैनिक कल्याण समिति बिलासपुर का एक प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मिला। समिति के जिला प्रधान सूबेदार प्रकाश चंद ने शहीदों के नाम पर बनाए जाने वाले वन विहारों की शुरूआत मुख्यमंत्री व विस उपाध्यक्ष से करवाए जाने की मांग की जिस पर प्रो. धूमल व रिखी राम कौंडल ने सहमति जताते हुए पूर्व सैनिकों के इस कदम की सराहना की। प्रो. धूमल ने कहा कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलने के साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह कदम प्रशंसनीय है। उन्होंने उपस्थित पार्टी कार्यकर्त्ताओं से भी पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री प्रो. धूमल ने घुमारवीं के प्रसिद्ध पलसोटी देवी मंदिर में शीश नवाया।

पंजाब केसरी, 17 मई, 2010

....

Externally Aided Projects & Bio Carbon Project

कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट का खुलासा शीघ्र

वर्ल्ड बैंक से आई आपत्ति पर भेजा जवाब, जल्द आएगा फैसला

करोड़ों के कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट के लिए अब राज्य सरकार को बस हां या न का इंतज़ार है। विश्व-बैंक ने कुछ अरसा पहले इस प्रोजेक्ट को लेकर जो आपत्ति लगाई थी, उसका जवाब भेजा जा चुका है। इसमें शामिल 35 विभिन्न प्रजातियों की 'ग्रोथ' से संबंधित विवरण मांगा गया था। खास बात यह कि प्रोजेक्ट से जुड़ी तैयारियां मिड हिमालय प्रोजेक्ट ने शुरू कर दी हैं। चयनित 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में से 2000 हेक्टेयर में पौधारोपण करने के बाद सफलता दर हेतु सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया गया है। प्रोजेक्ट में शामिल 35 प्रजातियों का ही इसमें पौधारोपण किया गया है। यदि सफलता दर में दिक्कतें आती हैं, तो बरसात में संबंधित प्रजातियों का फिर से पौधारोपण किया जाएगा। प्रोजेक्ट विशेषज्ञों का कहना है कि ये सभी तैयारियां इसलिए की जा रही हैं, ताकि मंजूरी मिलते ही प्रोजेक्ट को तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके। वैलिडेटर्स के चयन के लिए विश्व-बैंक की एक टीम भी पहुंच रही है। टीम देहरादून के संस्थान द्वारा की गई दोवेदारी को जांचेगी, इसके बाद तय होगा कि वैलिडैटर्स देहरादून के होंगे या फिर विश्व बैंक से ही रहेंगे। प्रोजेक्ट में कार्बनडाइऑक्साइड की फिक्सेशन की जांच हेतु 300 सैंपल प्लांट्स भी चिन्हित कर लिए गए हैं। वैलिडेटर्स इनमें लगाए गए 35 किस्म के पौधों की 'ग्रोथ' को मापकर यह तय करेंगे कि उन्होंने कार्बनडाइऑक्साइड कितनी सोखी है और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितनी उत्सर्जित की है। तकनीकी तौर पर यह आकलन होगा। उसी आधार पर राशि देय होगी।

प्रोजेक्ट के तहत पहले ही दस जिलों में किए गए पौधारोपण की सफलता जांचने के लिए सर्वे शुरू किया जा चुका है।

दिव्य हिमाचल, 1 मई, 2010

177 पंचायतों में कार्बन प्रोजेक्ट

मुख्यमंत्री धूमल बोले, सीधे लकड़ी बेचकर कमाई कर सकेंगे ग्रामीण

प्रदेश की 177 पंचायतों को बायो कार्बन उपयोजना के तहत लाया गया है। इससे ग्रामीण लकड़ी बेचकर सीधी कमाई कर सकेंगे। यह बात मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कही। मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने मंगलवार को मध्य हिमाचल जलागम विकास परियोजना के अंतर्गत राज्य प्राकृतिक स्रोत प्रबंधन की कार्यकारी परिषद् की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 365 करोड़ रुपए की मध्य हिमाचल वाटरशैड विकास परियोजना देश के अन्य राज्यों के लिए आदर्श योजना बनकर उभरी हैं, जिसको विश्व बैंक ने मई 2009 माह की रिपोर्ट में सराहा है।

उन्होंने कहा कि स्वां तटीकरण के कार्य को तब तक आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जब तक यह सतलुज नदी से न मिल जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में चैक डैमों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बायो कार्बन उपपरियोजना के तहत छोटे व मझौले किसानों को कार्बन क्रैडिट बेचकर अतिरिक्त आय सृजित करने के अवसर उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त ग्रामवासियों को बाजार में लकड़ी बेचकर सीधा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस पायलट परियोजना के लिए 177 ग्राम पंचायतें चिन्हित की गई हैं, जिनके अधीन 4003 हेक्टेयर भूमि लाई जाएगी। विधायक दिलेराम, उर्मिल ठाकुर, कर्नल इंद्र सिंह, रेणु चड्डा, मुख्य सचिव आशा स्वरूप ने परियोजना के अंतर्गत सभी कार्यकारी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अतिरिक्त मुख्यसचिव वन अभय शुक्ला ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अतिरिक्त मुख्य वन अरण्यपाल तथा हिमाचल जलागम विकास परियोजना के परियोजना निदेशक केएल कपूर ने परियोजना के कार्यों, लक्ष्यों एव उपलब्धियों के बारे में प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भीमसेन, प्रधान सचिव वित्त अजय त्यागी, कुलपति डॉ. केआर धीमान, प्रधान मुख्य वन अरण्यपाल डॉ. विनय टंडन सचिव ग्रामीण विकास आरडी धीमान, निदेशक कृषि जेसी राणा, निदेशक, पशुपालन डॉ. बी.सी. बिष्ट, योजना सलाहकार एसके शाद उपस्थित थे।

दिव्य हिमाचल, 23 जून, 2010

Forest Conservation

शीशम-तुनी की लकड़ी बेचेगा वन निगम

लकड़ी की दरें तय करने के लिए निगम ने बनाई कमेटी

राज्य वन निगम शीघ्र ही शीशम और तुनी की लकड़ी बेचेगा। लकड़ी की दर तय करने के लिए निगम प्रबंधन ने कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी जल्द ही रिपोर्ट बनाकर निगम प्रबंधन को सौंपेगी।

इसके बाद निगम के डिपुओं में शीघ्र ही फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी मिल सकेगी। इससे पहले निगम से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल लोग घरों के दरवाजे और खिड़कियां बनाने के लिए करते थे; लेकिन बेहतर फर्नीचर के लिए लकड़ी खरीदने के लिए लोगों को निजी डिपुओं का ही रुख करना पड़ता था। निगम के नए फैसले के बाद लोगों को निगम के डिपुओं में हर तरह की लकड़ी मिल सकेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक निगम के डिपुओं से मिलने वाली लकड़ी को न केवल आम लोग बल्कि फर्नीचर बनाने वाले छोटे उद्योगों के मालिक भी खरीद सकेंगे। लकड़ी की दरों पर शीघ्र ही फैसला लिया जाएगा। यह जानकारी राज्य वन निगम के प्रबंध निदेशक आरके गुप्ता ने दी है। उन्होंने बताया कि लकड़ी की दरें तय होने के बाद इसे शीघ्र ही निगम के डिपुओं में उपलब्ध करवाने के प्रयास शुरू हो जाएंगे।

अमर उजाला, 14 अप्रैल, 2010

वनसंपदा के संरक्षण को साथ दे जनता : धूमल

मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वनसंपदा के संरक्षण के लिए जनता का साथ मांगा। धूमल ने लोगों से अपील की कि वे बहुमूल्य वन संपदा और बस्तियों को आग से बचाने के प्रति स्तर्क रहें। उन्होंने कहा कि आगजनी की वारदातों में सामूहिक तौर पर नियंत्रण के लिए अग्निशमन कर्मियों का सहयोग करें।

मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने 64वें अग्निशमन दिवस के मौके पर शिमला में रिमोट कंट्रोल के जरिए हमीरपुर में नवनिर्मित अग्निशमन स्टेशन का उद्घाटन किया। हमीरपुर की विधायक उर्मिल ठाकुर ने अग्निशमन केंद्र भवन में वीडियो कान्फ्रैंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा भवन के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। विधायक ने कहा है कि इस अग्निशमन खुलने से इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है।

कार्यक्रम की शुरुआत बी. कमल कुमार ने सबसे पहले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत से किया। उन्होंने उपस्थित लोगों को अग्निशमन दिवस के बारे में अवगत करवाया। चीफ फायर अधिकारी शेर सिंह थापा ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कार्यक्रम ने अग्निशमन विभाग के 32 राष्ट्रपति पदक प्राप्त करने के लिए बधाई दी। उन्होंने बताया कि राज्य में 2009 में अग्निशमन विभाग द्वारा 1500 मामले दर्ज किए गए हैं। आगजनी की वारदातों में 125 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान व 37 लोगों की जाने गई है।

डीजीपी पुलिस जीएस गिल, विजिलेंस प्रमुख डीएस मन्हास, एडीजीपी सी.आई.डी. आईडी भंडारी, आईजी क्राइम ओसी ठाकुर, डीआईजी विजिलेंस एसपीएस वर्मा, डीआईजी साउथ रेंज अशोक शर्मा, उपायुक्त शिमला जेएस राणा सहित पुलिस विभाग के कई आलाधिकारियों ने समारोह में शिरकत की।

दैनिक जागरण, 15 अप्रैल, 2010

नाबार्ड देगा कटान का मुआवजा

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डैवलपमेंट के तहत अब तेजी से बनेंगी सड़कें

प्रदेश में नाबार्ड के तहत बनने वाली सड़कों के दौरान पेड़ काटे जाने पर मुआवजे का भुगतान नाबार्ड ही करेगा। ऐसी सड़कों को अब फॉरेस्ट क्लीयरेंस भी जल्द मिल सकेगी। प्रदेश में ऐसी सैंकड़ों सड़कें हैं जो फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण रुकी हुई हैं। इन सड़कों के निर्माण के दौरान जो भी पेड़ कटेंगे, उनका पैसा राज्य सरकार नहीं बल्कि नाबार्ड देगा। अभी तक यह पैसा सरकार को देना पड़ता था। पैसा समय पर जमा न होने कें कारण सड़कों के निर्माण में विलंब होता था।

नए पेड़ लगाने की भी जिम्मेदारी

नए निर्देशों के मुताबिक सड़कों की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डीपीआर) में ही पेड़ों की नेट प्रेजेंट वेल्यू (एनपीवी) और कंपनसेटरी अफॉरस्टेशन (सीए) की व्यवस्था करनी होगी। यानि जितने पेड़ कटेंगे, उसकी कीमत और इसकी भरपाई के लिए नए पेड़ लगाने का काम डीपीआई में ही सुनिश्चित करना होगा। इनके बगैर डीपीआर अधूरी मानी जाएगी। चालू वित्त वर्ष में लोक निर्माण विभाग नाबार्ड के वित्तीय सहयोग से सड़कों के निर्माण पर करीब 110 करोड़ की धनराशि खर्च करेगा। पिछले साल नाबार्ड की सड़कों पर करीब 108 करोड़ की धनराशि खर्च की गई थी। लोक निर्माण विभाग के एसई (वर्क्स) एमएस ठाकुर ने सड़क निर्माण में नई व्यवस्था लागू किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने माना कि पहली अप्रैल से शुरू हुए नए वित्त वर्ष में एनपीवी और सीए डीपीआर में ही सुनिश्चित करना होगा। उनका कहना है कि नाबार्ड के निर्देश पर अमल होना जल्द शुरू हो जाएगा। अब जो भी डीपीआर बनेगी, उसमें नाबार्ड के निर्देश फॉलो किए जाएंगे। कई क्षेत्रों में ग्रामीणों की ओर से सड़क के लिए ज़मीन न देने के कारण भी निर्माण रुका। सड़क निर्माण के लंबित मामले अधिक वन क्षेत्र वाले जिलों में ज्यादा हैं। सरकार ने विधायकों को निर्माण में तेजी लाने के लिए संबंधित मामलों में हस्तक्षेप के लिए भी कहा है।

दैनिक भास्कर, 19 अप्रैल, 2010

स्पीति में 'अपना वन-अपना धन' योजना शुरू

स्पीति घाटी में मरुस्थल विकास परियोजना व साझी वन योजना को मिली असफलता के उपरांत राज्य सरकार की 'अपना वन, अपना धन' योजना शीत मरुस्थल की काया पलट देगी। राज्य सरकार की इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष में 30 हज़ार हेक्टेयर भू-भाग पर पौधारोपण किया जाएगा। घाटी में चार दिवसीय प्रवास के आखिरी दिन सोमवार को विधायक राम लाल मार्कंडेय ने ताबो में भोजपत्र का पौधारोप कर योजना का शुभारंभ कर दिया। योजना के अंतर्गत शीत घाटी में 30 विभिन्न प्रजातियों के 33 हज़ार पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी वर्ष योजना के तहत लोसर में दस हज़ार भोजपत्र के पौधे लगाए जाएंगे।

दिव्य हिमाचल, 20 अप्रैल, 2010

वन विभाग प्राकृतिक वन सम्पदा के संरक्षण के प्रति कृतसंकल्प : विनय टंडन

वन विभाग राज्य में उपलब्ध अपार प्राकृतिक वन सम्पदा के संरक्षण के प्रति कृतसंकल्प है तथा राज्य के जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्र किन्नौर जिले में उपलब्ध चील गोजा प्रजाति के संरक्षण एवं रोपण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह बात प्रधान प्रमुख अरण्यपाल विनय टंडन ने रविवार को यहां वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में कही।

प्रधान प्रमुख अरण्यपाल वन्य प्राणी अश्वनी गुलाटी ने कहा कि चीलगोजा के प्राकृतिक पौधों के संरक्षण के साथ-साथ इसके रोपण पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि चीलगोजा क्षेत्र में वृद्धि की जा सके। इससे लोगों के आय के और अधिक साधन उपलब्ध हो सकें।

सामाजिक अर्थशास्त्री डॉ. रिंकी सरकार ने जिला किन्नौर के गांवों में चीलगोजा पर किए एक अध्ययन पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने चीलगोजा के पारिस्थितिकीय एवं आर्थिक महत्त्व के बारे में भी बताया।

प्रधान सचिव सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य नरेंद्र चौहान, प्रधान सचिव युवा सेवाएं एवं खेल वी.सी.फारका ने कार्यशाला में अपने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए।

अजीत समाचार, 3 मई, 2010

Concern over Chilgoza pines

Foresters and scientists deliberated at a day's workshop here on Sunday over ways to conserve the rare Chilgoza pines of Kinnaur district, which are apparently threatened by changing weather patterns and construction of hydropower projects.

Rinki Sarkar, a social economist, who had done a study on village specific livelihood and regeneration studies of Chilgoza pine, highlighted the ecological and economic importance of the rare forestry project. She also gave a detailed presentation about conservation solutions for the rare pine forests of Kinnaur.

The edible pine, which grows only in some high altitude zones of the planet, including some areas of Pakistan, Afghanistan and Kinnaur in India, is threatened as the region is feeling the growing impact of global warming. Ashwani Gulati, principal chief conservator, wildlife, emphasized on new planting techniques for Chilgoza saplings so that natural regeneration could be supplemented by artificial regeneration.

Presiding over the workshop, Viney Tandon, principal chief conservator, forests, said every effort would be made to conserve and regenerate Chilgoza species.

The Time of India, May 3, 2010

वन भूमि कब्जाई तो खैर नहीं

अतिक्रमण रोकने के लिए नए नियम लागू

10 बीघे से ज्यादा कब्जे पर एफआईआर

प्रधान मुख्य अरण्यपाल तय करेंगे दाम

दस बीघे से ज्यादा वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से सरकार अब और ज्यादा सख्ती से निपटेगी। अतिक्रमण करने वालों पर बिना किसी हीला हवाली के एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके अलावा यदि कोई कंपनी वन भूमि में दस लाख से अधिक का नुकसान पहुंचाती है, तो उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई कर सकेगी। संरक्षित क्षेत्रों जैसे वन्य प्राणी अभ्यारण्यों में अतिक्रमण करने पर अब और भी कड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है।

वनों में अवैध कटान और अतिक्रमण रोकने के लिए प्रदेश सरकार के नए नियम लागू हो गए हैं। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अवय शुक्ला ने इन नियमों की प्रतिलिपियां सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों, डीआईजी, विजिलेंस के डीजीपी, अभियोजन निदेशालय के निदेशक को भेज दी है। सरकार ने प्रदेश के डीएफओ रैंक के अधिकारियों को एक और शक्ति दे दी है। यदि डीएफओ को लगे कि वनों में अपराध करने वाले व्यक्ति से वन विभाग की बजाए पुलिस बेहतर तीरके से निपट सकती है तो वह पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करा सकता है। उन्हें इसके लिए वन विभाग के अरण्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। सरकार ने डैमेज रिपोर्ट काटने की शक्तियां भी रेंज अफसरों को दे दी हैं। रेंज स्तर पर ही इन मामलों का निपटारा किया जा सकेगा, लेकिन इसकी मासिक रिपोर्ट संबंधित डीएफओ को ही भेजनी होगी। सरकार ने वन भूमि पर अवैध डंपिंग को लेकर मुआवजा तय करने के लिए अरण्यपाल को अधिकृत किया है। वन उत्पादों का मूल्य अब हर साल प्रधान मुख्य अरण्यपाल निर्धारित कर सकेंगे, जबकि लघु वन उत्पादों का मूल्य अरण्यपाल ही निर्धारित कर पाएंगे। अभी तक ये मूल्य प्रदेश सरकार तय करती है।

वन विभाग के आठ थाने और : वन

विभाग ने भी अपने वन थाने खोल रखे हैं। इनकी संख्या पूरे प्रदेश में आठ है। ये उन्हीं जगहों पर खोले गए हैं, जो इलाके वन अपराधों के दृष्टिकोण से अतयंत संवेदनशील हैं। सरकार इसी वित्त वर्ष में आठ और वन थाने खोलेगी।

दैनिक भास्कर, 17 मई, 2010

अवैध कटान को लेकर विभाग सतर्क

अफसरों की बैठक बुलाकर जल्द तय होंगी रणनीति

ऊपरी शिमला के कई जंगलों में चल रही वन विभाग व विजिलेंस की संयुक्त मुहिम में उजागर हुए अवैध वन कटान के मामलों के बाद वन विभाग गंभीर है। मामला सरकार के पास पहुंच गया है और वहां से नए दिशा-निर्देश जारी हुए हैं। जंगलों में इस तरह से हो रहे बड़े पैमाने पर अवैध वन कटान पर रोक लगाने के लिए अब अधिकारियों की कसरत करवाने का निर्णय लिया गया है। वन विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि जल्दी ही इन मामलों पर अधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें विस्तृत जानकारी तो ली ही जाएगी, बल्कि इस पर रोक की रणनीति भी बनेगी। बताते हैं कि वन विभाग के अधिकारियों को महीने में कई दफा उनके एरिया में आने वाले जंगलों में जाने के लिए बाध्य किया जाएगा। अभी तक निचले स्तर के अफसर या कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं कर पाते। लिहाजा अब सभी पर बाध्यता होगी, जिससे जंगलों को सुरक्षित किया जाएगा। यहां जान लें कि इससे पहले भी वन विभाग ने अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दिए थे कि वे फील्ड में जाना तय बनाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिससे निचले स्तर पर कर्मचारी भी गंभीरता से काम नहीं करते। ऐसे में जंगलों में अवैध वन कटान बड़ी संख्या में हो रहा है, जिसकी किसी को कानों-कान खबर नहीं लगती। कई जगह वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से ऐसे मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। पता चला है कि प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव वन ने ऊपरी शिमला के जंगलों में सामने आए मामलों पर विभाग से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। बता दें कि ऊपरी शिमला के जंगलों में विजिलेंस और वन विभाग की संयुक्त मुहिम के तहत अभी तक दो हज़ार से ज्यादा ऐसे पेड़ मिले है, जिनका अवैध रूप से कटान किया गया है। कोटखाई और ठियोग के जंगलों में कई कटे हुए पेड़ों के ठूंठ भी मिले हैं, जिससे साफ है कि कई सालों से यहां अवैध कारोबार चल रहा है। शिमला जिला में अधिकांश स्थानों पर लोगों ने जंगलों में सेब के पौधे लगाकर उस ज़मीन को अपनी संपत्ति में जोड़ दिया है, क्योंकि राजस्व रिकार्ड में पूरा खाका सही नहीं है, लिहाजा लोग वन भूमि को कब्जाकर बैठे हैं।

दिव्य हिमाचल, 19 मई, 2010

हर माह जंगलों में जाकर जायजा लेंगे अधिकारी

अवैध कटान और आग से बचाने की तैयारी

मासिक रिपोर्ट में दौरों का विभाग को भेजना होगा ब्योरा

सीएफ से लेकर रेंज अधिकारी तक की लगेगी ड्यूटी

वन विभाग के अफसर अब कार्यालयों में आराम नहीं फरमा सकेंगे। सभी अधिकारियों का हर महीने जंगलों में जाकर वन संपदा का जायजा लेना अनिवार्य होगा। सीएफ से लेकर रेंज अधिकारी तक को दौरा कर रिपोर्ट तैयार करनी होगी। हर माह के अंत में विभाग को मासिक रिपोर्ट भी भेजनी होगी। विभाग ने कोटखाई रेंज में सामने आए अवैध कटान के बड़े मामले के बाद उक्त फैसला लिया है। विभाग इसका खाका शीघ्र ही तैयार करेगा। इसमें किस अधिकारी को कितने दौरे करने हैं, इसका विस्तार से खाका तैयार किया जाएगा।

सूत्र बताते हैं कि कोटखाई रेंज के तीन जंगलों में भारी मात्रा में अवैध कटान का मामला सामने आया है। विभाग का मानना है कि यह कटान एक या दो दिन का नहीं, बल्कि लंबे समय से जंगल में अवैध कटान हो रहा था। वन अधिकारी और कर्मचारी जंगलों का दोरा रैगुलर कर रहे होते तो हज़ारों पेड़ कटने से बच सकते थे। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों की वन संपदा को नुकसान हुआ है। इस मामले की जांच पूरी होने के बाद विभाग शीघ्र ही उच्च स्तरीय बैठक कर उक्त योजना का खाका तैयार करेगा।

इसके बाद जंगलों का दौरा करना अधिकारियों के लिए अनिवार्य होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) अभय शुक्ला ने माना कि जंगलों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को जिम्मेवारियों सौंपी जाएंगी। इससे अवैध कटान को रोकने में सहायता मिलेगी और वनों को आग से बचाए रखने में काफी मदद मिलेगी।

अमर उजाला, 19 मई, 2010

10 more 'van thanas' to come up

Encouraged by the success of the four "van thanas", the state

government has decided to set up 10 more such "thanas" in sensitive areas.

At present, eight "van thanas" were functional in the state out of which Habban, Mohal, Balu and Chhaila have been in operation for the past over one year. In all, 50 cases of illicit felling, timber smuggling, illegal saw mills and unauthorised extraction of sand and stone were detected by these thanas. Timber worth over Rs. 5 lakh was seized in 31 recoveries and four illegal saw mills were unearthed along with timber worth over Rs. 2 lakh. Besides, five cases of smuggling were also detected.

Three more thanas were subsequently set up at Bassi in Bilaspur, Tikker in Rohru and Nagrota Suriyan in Kangra. The 10 new thanas are proposed to be set up at Theog in Shimla, Deokhand in Mandi, Puruwala in Sirmour, Naggar and Jhibbi in Kullu, Kalel in Chamba, Nankheri in Shimla, Bhagarwan in Kangra, Talhera in Una and Ropa in the Great Himalayan National Park.

Each "van thana" is headed by a block officer supported by five-six forest guards and three-four forest workers. Instead of a solitary guard patrolling a particular beat, thana staff operates in a bigger area and team are equipped with vehicles, weapons, wireless communication facilities and mobile phones.

The department already has flying squads but these have not proved very effective. "Van thanas" enable the department to concentrate on select areas where the timber mafia is more active. With the road network extending to every nook and corner of the state, timber smuggling has become easier and economically fare more attractive.

The Tribune, May 20, 2010

....

गांवों के सड़क किनारे भी लगेंगे पौधे

राज्य में सड़कों किनारे पौधे शहरों में ही नहीं बल्कि गांव में भी दिखेंगे। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस योजना को लागू करने का फैसला लिया है। विभाग का मानना है कि इस सड़कों के किनारे लगाए पौधों को ज्यादा बेहतर तरीके से बचाया जा सकेगा।

यहां वाहनों की आवाजाही कम रहती है, इसलिए प्रदूषण काफी कम मात्रा में रहता है। इसलिए यहां पौधा लगाने से पर्यावरणप संरक्षण में काफी सफलता मिलेगी। इससे पहले निर्माणाधीन राष्ट्रीय और राज्य मार्गों के किनारे इन्हें लगाने का काम चल रहा है। मुख्य संसदीय सचिव वीरेन्द्र कंवर ने इसकी पुष्टि की है।

प्रदेश के गावों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों को हरा भरा रखने की तैयारी है। इसमें एनएच ही नहीं बल्कि गांवों कस्बों की सड़कों के किनारे पौधे रोपे जाएंगे। सड़क किनारे लगाए जाने वाले पौधे को विभाग अपनी नर्सरी में तैयार करेगा। पौधों की देखरेख बेहतर तरीके से हो सके, इसलिए स्थानीय लोगों की मदद भी ली जाएगी। पौधे एक बार लगाने के बाद इसे स्थानीय लोगों को सौंप दिया जाएगा। विभाग अपनी ओर से लोगों की मांग पर मदद मुहैया करवाएगा। मुख्य संसदीय सविच लोक निर्माण विभाग वीरेन्द्र कंवर ने माना कि ग्रामीण सड़कों के किनारे भी पौधे लगाने की तैयारी है। इससे गांव की ओर जाने वाले रास्ते हरे-भरे दिखाई देंगे और पर्यावरण को बचाए रखने में भी काफी मदद मिलेगी।

अमर उजाला, 1 जून, 2010

....

Ex-Servicemen on 'green' mission

After bidding farewell to arms, ex-servicemen have turned, "eco-soldiers" who have charted a success story in greening barren hills along the Sutlej catchments.

They have accomplished in three years' time what the HP forest department could not do in decades, sending a befitting message on the occasion of World Environment Day tomorrow with its theme, "Biodiversity : Ecosystem management and green economy".

The odd contigent of 100 ex-servicemen, who joined territorial Army's 133 Eco Task Force, has already greened 280 hectares of barren hill sides along the Sutlej, the catchments area treatment (CAT) plan of the 800 MW Kol Dam project.

The task force has scripted a survival rate of 85 per cent trees which is much higher than the dismal 20 to 30 per cent trees calimed by the state forest department. In view of this success, it has been assigned the task of greening 2,500 hectares of barren areas under CAT plans of Larji, Parbati and Allian-Duhangan power projects in Mandi-Kullu region and parts of the chamba district, utilising the CAMPA funds.

Major Ajay Sangvan, Commandeer, 133 Task Force, said, "We first fence the areas and then raise nursery of local samplings for plantation. We started in 2007 and have planted around 2,000 saplings in Tattapani in Mandi district successfully."

The task force is not only greening the barren hills, it is also sensitising villagers about the importance of greenery in today's life. Moreover, it has also developed camping sites for

visitors to promote eco-tourism in the area that will raise additional income for villagers.

Col DS Chauhan, in charge of the task force, said, "Himachal declared its nine districts as drought-prone. Drinking water problem will aggravate as rains have been scaty. Villagers are now realising that we are planting trees for the benefit."

He said they did a recce of 1,000 hectares of area assigned to them in the Kullu-Mandi region under CAT plans of the Beas. "We are recruiting a separate eco-task battalion to afforest Larji and other catchments. We target to plant saplings in 250 hectares of land in a year." he added.

The forest department was in a fix over the use of CAT plan funds after the Supreme Court constituted the CAMPA to utilise the funds for the purpose. The funds were diverted to other purposes, leaving deserted areas all the more barren, sources revealed.

Forest Conservator BD Suyal said the state was getting Rs. 30 crore CAMPA funds. "The HPSEB has given Rs. 12.8 crore for afforestation of Larji area that fall partly in Kullu and Balichowki and Panarsa range in Mandi along the Beas," he said.

The Tribune, June 5, 2010

....

सिकुड़ते वन क्षेत्र पर चिंता

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि मानव जरूरतों के हिसाब से यह संसार पर्याप्त है। मगर लालच के हिसाब से काफी नहीं। यह उक्ति सही बैठती है जंगलों का अवैध कटान करने वाले अतिक्रमणकारियों पर जो सैंकड़ों बीघा जमीन पर कब्जा करने के बाद भी संतुष्ट नहीं दिखते हैं। जुब्बल क्षेत्र की हालत भी कुछ ऐसी ही बन गई है। इस क्षेत्र के जंगलों का घनत्व लगभग 19 हजार प्रति हैक्टेयर है जोकि अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।

जुब्बल के राजा भगत चंद्रा के शासनकाल में टिकाऊ विकास पर जोर दिया जाता था और यदि एक पेड़ काटना होता तो उसके बदले 10 पेड़ पहले ही लगा दिए जाते थे मगर वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है जिसे लेकर गैर-सरकारी संस्थान व स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। जंगलों की बात करें तो हर वर्ष न जाने कितने पेड़ों की बलि चढ़ती है बल्कि जंगलों में पाई जाने वाली, वनस्पति को भी क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। शरारती तत्व भी जंगलों में आग लगाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार की वन लगाओ रोजी कमाओ योजना एक प्रशंसनीय योजना थी जिसे बाद वाली सरकारों ने भुला दिया है। क्षेत्र के पर्यावरणविदों एवं प्रकृति प्रेमियों का कहना है कि वनों का कटान 1980 के बाद बड़ी तेजी से हुआ जिस कारण जंगली जानवर मजबूरन रिहायशी क्षेत्रों की ओर रूख कर रहे हैं। यदि हम वर्तमान समय में कोई ठोस उपाय नहीं करते है तो आने वाली पीढ़ियां केवल पुस्तकों, टी.वी., अखबारों व कम्पयूटरों पर ही दुर्लभ वृक्षों, पक्षियों एवं जानवरों की तस्वीरें देख पाएंगे।

शिमला केसरी, 9 जून, 2010

....

Shimla to irrigate forests to revive its deodars

Climate Change : Low survival rate of Saplings raises concerns

Erratic changes in the weather cycle of Himachal Pradesh, dominated by long spells of drought, have posed a though situation for the revival and conservation of deodar trees in the state capital, Shimla.

Due to the prevailing dry conditions, conservationists and foresters are considering a dedicated irrigation plan for the fresh deodar plantations to be raised across the Shimla forests, under the Deodar Revival Projects started suring the monsoon of July 2009.

It will be a one-of-its-kind experiment to sustain the fresh saplings with regular irrigation in the wild.

In the first year of the project in Shimla, 5,000 saplings had been planted, but only 60 per cent could survive till March 2010 due to drought. The latest figure of survival could be much lower as Shimla saw an unusally dry and warm summer, which started early in March and is still continuing.

The 2009 monsoon was weak and the dry spell continued throughout the winter months too, recording nearly 90 per cent deficient rainfall.

According to the forest department's proposal. sources say, nearly 10,000 deodar saplings are to be planted by the year end and nearly Rs. 5 to Rs. 10 lakh will have to be spend on their irrigation, by transporting water to the forests through tankers.

Conservator of Forests, Shimla Circle, S.K. Sharma says: "Through irrigation of deodar plantations in the wild is unheard of elsewhere, it seems crucial for the revival of the trees here."

Shimla is identified with its thick deodar forests but the natural regeneration of trees in the wild has been marred by the changed weather cycle and the construction boom in the recent past.

Sticky secretion : Trees were under extreme stress in dry and

warm winter, says study

Another impact of the climatic change was seen in the winter of 2008-09 when the deodar and kail trees in Shimla and along the Sutlej river basin a secreted a sticky liquid, which had spread unrest among people. The sticky secretion could be felt like rain while walking in the woods. Director, Himalayan Forest Research Institute, Mohinder Pal says they commissioned a study to research this particular ecological phenomenon. "We saw the secretion from deodar trees, which require cold and moist weather, in light of the climate change. It seemed like a physiological process where the trees were under extreme stress in the dry and warm winter."

The Indian Express, 15 June, 2010

....

Labour body questions selective nod to felling of dead trees in eco-zone

A conflict seems to be emerging in the Himachal Pradesh forest department over the felling of salvage (dead) trees in the forests surrounding the Great Himalayan National Park (GNHP) in Kullu district the GHNP is under the protected area network.

While the forest department has finally turned down the proposal of the HP Forest Corporation to remove salvage trees in the four forests-Bashleu, Shirdunga, Mandarwachi and Tispur-in the vicinity of the GHNP, the HP Timber Extraction Labour Organisation has questioned why salvage removal was allowed in Gandiyol and Thanohar forests, which is also in located in the same eco-zone.

In its complaing, the organisation has claimed that as many as 820 rai tos and Kharsu trees in Shridunga, 823 rai tos in Mandarwachi and 1,421 kail and rai tos trees in Tispur forests were marked for removal in 2005. According to market rates of the year 2008-09, the total worth of the trees was Rs. 3.49 crore, of which the forest department was to get a royalty of Rs. 1.38 crore.

"The government is now even denying that it had done any marking. It is not allowing any salvage removal in these forests on the plea that this is 'c-sensitive zone', but this applies to Gandiyol and Thanohar forests too. This raises suspicion and smells of vested interest," says Jog Dhian Thakur, president of the association.

These four forests were handed over to Seraj Circle for eco-development project in 1995 for five years but were never given back to the Banjar circle, even as there is no official approval for final inclusion of forests in the new circle.

Principal Chief Conservator of Forest Vinay Tandon, however, has denied any marking in the four forest and has quoted report (documents with The Indian Express) of GHNP conservator that says: "As the trees in these forests are on steep slopes. they cannot be marked for felling. Another reason is dependence of wildlife on these forests during winters as they fall in the eco-zone of GHNP. The dry trees here can be used by the local villagers for mundane use which would help in keeping away human interference from the GHNP."

Tandon's disapproval was conveyed to the government in a letter sent on June 18. The forest department has not quoted reasons for allowing salvage removal in Thanohar and Gandyoli, but has accepted that they fall in the ecozone of the GHNP. The government's final response on the issue is still awaited.

The Indian Express, 24 June, 2010

....

पौधरोपण और तारबंदी के लिए मनरेगा से पैसा

हाईपावर कमेटी की बैठक में सरकार ने लिया फैसला

वन विभाग की जमीन पर भी पौधरोपण और तारबंदी के लिए अब मनरेगा से पैसा मिलेगा। इसके साथ शर्त भी रखी है कि यह कार्य केवल नए पौधारोपण में होगा। इसके लिए विभाग का प्लांटेशन प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। इसका 60 प्रतिशत काम मजूदरों से और 40 प्रतिशत कार्य मैटेरियल कंपोनेंट से करना पड़ेगा। ग्रामीण विकास विभाग ने प्लांटेशन प्रोजेक्टों को मनरेगा में शामिल करने की इजाजत दे दी है।

हालांकि वन विभाग पुरानी प्लांटेशन में भी तारबंदी करने की मंजूरी मनरेगा से ही चाह रहा था। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि पिछले महीने 24 मई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाईपावर कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें पौधरोपण और भूमि विकास के कार्य मनरेगा के तहत करने पर चर्चा की गई थी। भूमि विकास पहले ही मनरेगा में शामिल किया गया है। इसमें तो लघु और सीमांत किसान भी अपनी निजी भूमि में भूमि विकास की गतिविधियां शुरू कर सकते हैं। लेकिन वन भूमि में पौधरोपण और तारबंदी की व्यवस्था अभी तक नहीं थी।

इस बाबत वन विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग को पत्र लिखा था। इसमें कहा गया था कि पौधरोपण के बाहर तारबंदी करने की गतिविधि भी मनरेगा में

जोड़ी जाए। यह मामला सरकार के ध्यान में लाया गया। इसी संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने नए निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार मनरेगा में पौधों की तारबंदी के लिए अलग से कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। तारबंदी उसी हालत में हो सकती है यदि दूसरी शर्तें भी पूरी की जाए। इसमें पौधरोपण का मजदूरों के माध्यम से करवाना होगा। इसके साथ ही मैटेरियल कंपोनेट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इस निर्देशों की प्रतियां सभी जिलों के उपायुक्तों, डीआरडीए के परियोजना अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों को भी प्रेषित की गई है। इसके अलावा वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इसकी अलग से सूचना दी गई है।

दैनिक भास्कर, 28 जून, 2010

....

हिमाचल में पौधरोपण का लक्ष्य बढ़ेगा

सालाना 48 हजार हैक्टेयर भूमि पर लगेंगे पौधे

केन्द्र सरकार हिमाचल में पौधरोपण के कोटे में बढ़ोतरी कर दोगुना करने की तैयारी में है। इसे 24 हजार हेक्टेयर से बढ़ाकर 48 हजार हेक्टेयर करने की उम्मीद है। इसके लिए वन विभाग ने भी अंदरूनी तौर पर तैयारी शुरू कर दी है।

केन्द्र ने राज्यों का पचास फीसदी भूमि वन क्षेत्र के तह लाने के लक्ष्य को देखते हुए उक्त तैयारी शुरू की है। वर्तमान में विभाग प्रदेश में बरसात और सर्दियों के सीजन में पौधयारपेण करता है। सर्दियों के सीजन में बारिश न होने के कारण कई बार पौधरोपण का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता है। इसे देखते हुए साफ है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए विभाग को बरसात के सीजन में लक्ष्य को हासिल करना होगा। सूत्र बताते हैं कि चालू वर्ष के सीजन में पुराने लक्ष्य के तहत ही पौधरोपण किया जान प्रस्तावित है। वर्तमान में हो रहे पौधरोपण को भी विभाग पूरी तरह से संरक्षित नहीं कर पा रहा है। ऐसे में लक्ष्य बढ़ने के बाद इनका संरक्षण करना काफी मुश्किल हो सकता है। नए पौधों की सफलता दर को बढ़ाने के दावे तो विभाग अमूमन करता है, लेकिन हर साल 24 हजार हेक्टेयर पर लगे पौधों में से तीस फीसदी भी बच नहीं पाते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) अभय शुक्ला ने माना कि पौधरोपण का लक्ष्य बढ़कर दोगुना हो सकता है। केन्द्र सरकार इस पर विचार कर रही है। इसकी सूचना मिली है, लेकिन केन्द्र की ओर से लिखित सूचना अभी तक नहीं मिली है।

अमर उजाला, 30 जून, 2010

....

Forest Fire Management

Forest fires : HP on high alert

Of the 151 fire incidents reported in last week, at least 95% were forest fires

With the temperatures remaining nearly 10-12 degrees Celsius above normal, amid the extreme dry weather conditions, forest fires are spreading fast across the state. Nearly 150 fire incidents across six districts of the state were reported in the last one week.

And the summer has only begun.

In a meting with Principal Secretary (Home) Subhash Negi, Additional Director General of Police (Home Guards and Fire Services) B. Kamal Kumar sought the home department's intervention to seek more cooperation from the forest department and urban local bodies to tackle the situation.

"In the last one week, 151 cases of fire were reported and at least 95 per cent of them were forest fires & in Shimla, Solan, Mandi, Sirmaur and Dharamshala. Most of them were reported from areas situated far from the nearest fire stations. As a result, the fire had multiplied manifolds by the time fire tenders accessed the forests. We feel the forest department and municipal committees should take more responsibility in preventing fire incidents, which can be reduced by 60 per cent," said.

The fires reported in the last couple of days from forests in Kuthar areas of Solan district and Kharapathar, Sheelghat, Narkanda and Taradevi area in Shimla are still raging.

The forest department, meanwhile, is set to launch a massive 'forest path clearing drive' to prevent fires.

The process to set a weekly system of reporting fire incidents from across the state, in order to put in place a mechanism to fix responsibility, is already on.

"A general assessment of forest fires shows that usually the fire starts from areas near a road or access point to the forest like trails and bridle paths, due to human errors- lit cigarette butts or matches thrown in the woods. A large work-force is set to be

deployed on temporary basis across all forest divisions of the state to clear pine needles and other inflammable forest discard at least 10 metres on each side of the forest trails and bridle paths to prevent fires. The action is set to be extensive in areas with Chir forests (highly inflammable tree species)," said Principal Chief Conservator of Forests Vinay Tandon.

Teh forest clearance will be taken up as an ongoing process from April, 15 to June, 15. Additional deployment of 10 Home Guards at Divisional Forest Officer level in more fire-prone districts is also being worked out.

According to official information the fire department has 22 fire stations that have 73 vehicles and a majority of them are over 25 years old. There is a proposal to add 25 new fire vehicles to the fleet this year, say government officials.

The Indian Express, April 17, 2010

....

अब आग पर नज़र रखेगा सैटेलाईट

वनों में आग की सूचना संदेश के जरिए पहुंचेगी अधिकारियों को

वन विभाग के अधिकारियों ने फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में करवाय अपना पंजीकरण

गर्मियों के सीजन में वनों में आग लगने के अनेक मामले सामने आते हैं जिससे एक ओर यहां तापमान बढ़ता है, वहीं दूसरी ओर बहुमूल्य वन संपदा भी अग्नि की भेंट चढ़ जाती है और अनेक मामलों की जानकारी तक वन विभाग के अधिकारियों को नहीं मिल पाती। वनों में आग की घटना रोकने व आग की घटना की सूचना तुरंत संबंधित क्षेत्र के अधिकारी तक पहुंचाने के लिए केंद्रीय वन विभाग के फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विंग देहरादून ने वनों में लगने वाली आग की जानकारी जुटाने व आग की जानकारी तुरंत प्रभाव से संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को मोबाईल के जरिए भेजने का शुभारंभ किया है। इसके लिए वन विभाग के अधिकारियों ने फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के साथ अपना पंजीकरण मोबाईल नंबर सहित करवाया है। इस पंजीकरण के माध्यम से अधिकारी अपने क्षेत्र, प्रदेश, पूरे देश भर की वनों में आग लगने की घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अधिकारियों को लॉन्गीच्यूट व एल्टीच्यूट के माध्यम से आग लगने की लोकेशन के बारे में जानकारी देता है। वनों में आग लगने की घटनाओं से अपडेट होने से आग पर काबू पाना आसान हो रहा है। जिला वन अधिकारी आरके राज ने बताया कि संदेश के जरिए वनों में आग लगने की घटना की जानकारी मिलने से आग की घटनाएं रोकने में आसानी हो रही है। उन्होंने बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो वनों की आग पर नज़र रख रहा है उसके द्वारा जिला में वन क्षेत्र में आग लगने की स्थिति में लोकेशन का संदेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि अनेक बार आग लगने की घटना की जानकारी देरी से मिलती थी, जो अब समय पर उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि जिला के वन विभाग से संबंधित फील्ड स्टाफ ने अपना पंजीकरण करवाया है।

अजीत समाचार, 23 अप्रैल, 2010

....

आगजनी की रपट नहीं काम चाहिए

जेपी नड्डा बोले, वनों में स्पॉट पर मौजूद रहें कर्मी

वन मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जंगलों में आग लगने पर विभागीय कर्मियों को मौक पर मौजूद रहना होगा। अंब में संवाददाता सम्मेलन में वन मंत्री ने साफ कहा कि आगजनी की महज रिपोर्ट में काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि वनों को आग से बचाने के लिए विभाग को भारी मात्रा में ज़रूरी साजो-सामान मुहैया करवाया गया है। उन्होंने कहा कि वन अधिकारियों के फोन का खर्च भी प्रदेश सरकार वहन कर रही है। विभागीय कर्मचारियों को जंगलों में आग की रिपोर्ट नहीं, बल्कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिस भी बीट के जंगल में आग लगती है, उस क्षेत्र के लोगों को विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस स्थान पर आग के कारण सरकारी संपदा का नुकसान हुआ है, नजदीकी लोगों से आग के कारणों की जांच-पड़ताल की जाएगी। आग लगाने का जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है, सरकार उसके टीडी अधिकार, जंगल राइट अधिकार के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है।

वन मंत्री जेपी नड्डा ने गंगोट मोईन (कांगड़ा क्षेत्र) पंचायत हिमाचल परिवार द्वारा आयोजित संगोष्ठी में शिरकत की। संगोष्ठी का विषय 'ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज' रहा। इस दौरान उन्होंने महंगाई के लिए कांग्रेस को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि देश में अनाज की कमी नहीं है। इन दिनों 253 लाख टन अनाज सड़

रहा है। इस मौके पर मुख्यातिथि इंद्रेश कुमार परिषद् प्रचारक एवं समाजसेवी ने भी ग्रामीण स्तर पर सुधार करने की बात पर बल दिया। उपाध्यक्ष जल प्रबंधन बोर्ड प्रवीण शर्मा ने भी विचार व्यक्त किए।

दिव्य हिमाचल, 1 मई, 2010

जंगलों में आग की सूचना एसएमएस पर

फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून ने सभी वन सेटेलाइट से जोड़े

धू-धू कर जल रहे जंगलों में लगी आग की सूचना अब वन विभाग के अधिकारियों को मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से मिलेगी। प्रदेश के सभी वन मंडल व वन परिक्षेत्र कार्यालय फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्यालय देहरादून से जुड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक वन विभाग के अधिकारियों को फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया मोबाईल पर मैसेज द्वारा संदेश देगा कि वन मंडल के किस क्षेत्र में आग लगी है। फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रदेश के सभी जंगलों को सेटेलाइट से जोड़ दिया है। जेसे ही किसी क्षेत्र में आगजनी की घटना होगी, तुरंत ही सेटैलाइट के माध्यम से फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के देहरादून स्थित कार्यालय को सूचना मिलेगी। सूचना मिलते ही कार्यालय से संबंधित क्षेत्र के वन अरण्यपाल, वन मंडल अधिकारी तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी के मोबाइल पर मैसेज आएगा कि किस क्षेत्र में आगजनी हुई है। मैसेज मिलने के उपरांत वन अधिकारी इंटरनेट पर संबंधित क्षेत्र को सर्च कर आगजनी वाले एरिया की पहचान करेंगे। जानकारी के मुताबिक मोबाइल के माध्यम से उन्हीं वन अधिकारियों को एसएमएस जाएगा, जिन्होंने अपना पंजीकरण फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के देहरादून स्थित कार्यालय में करवाया हो। जानकारी के मुताबिक अप्रैल माह से सेटेलाइट से जुड़े वन अधिकारियों को कुछ ही दिनों में दो दर्जन से अधिक आगजनी की घटनाओं की सूचना फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के कार्यालय से एसएमएस से मिली है। वन मंडल अधिकारी नाहन एचवी कथूरिया ने बताया कि सेटेलाइट से जुड़ने के बाद विभाग को आगजनी की सूचनाएं फोरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून से एसएमएस के माध्यम से मिलनी शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि फायर सीजन के दौरान जिला में अब तक आगजनी के 17 मामले प्रकाश में आए हैं। उन्होंने बताया कि विभाग ने वन मंडल में एक कंट्रोल रूम बनाकर एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो आगजनी पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने कहा कि खास तौर से उन क्षेत्रों में इसका लाभ मिलेगा, जहां सड़क आदि की सुविधाएं न होने के कारण आगजनी की सूचनाएं कई-कई दिनों तक नहीं मिलती थीं। अब सेटेलाइट द्वारा तुरंत ही सूचना मिल जाती है।

दिव्य हिमाचल, 6 मई, 2010

Global Warming/Climate Change

जून में बुरांस के फूल

मौसम परिवर्तन के साथ-साथ पेड़ पौधों पर खिलने वाले फूलों ने भी समय बदला

जाखू की पहाड़ी पर खड़े बुरांस के पेड़ों पर खिल रहे हैं लाल रंग के फूल

आमतौर पर मार्च-अप्रैल है इनके खिलने का समय

ऐसा समय आने वाला है कि जब आपको नवंबर-दिसंबर के महीने में जंगलों में लाल बुरांस के फूल और आम के पौधों पर जून-जुलाई में बौर दिखाई देंगे। जी हां, यदि समय रहते नहीं चेते तो ऐसी स्थिति आने ही वाली है। आमतौर पर मार्च-अप्रैल में बुरांस पर आने वाले लाल फूल इन दिनों खिल रहे हैं। यकीन न आए तो जाखू की पहाड़ी चढ़िए वहां देवदारों के बीच खड़े बुरांस के पेड़ों में लाल रंग के फूल दूर से ही दिखाई देंगे।

मौसम परिवर्तन का असर अब पेड़-पौधों पर भी दिखने लगा है। इसके साथ ही पेड़-पौधों पर खिलने वाले फूलों का समय भी बदल गया है। आमतौर पर मार्च-अप्रैल में खिलने वाले बुरांस के फूल दो माह खिल रहे हैं।

पर्यावरणविद्, कृषि व बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग है। दरअसल बुरांस के फूल अमूमन मार्च-अप्रैल में खिलते हैं। हालांकि उस समय बहुत कम पेड़ों पर फूल खिले। ठीक उसके बाद शिमला में बारिश हो गई जिसके कारण तापमान नीचे आ गया। जिन पेड़ों पर फूल नहीं आए थे अब यह फूलों से आच्छादित हैं। ये फूल पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। शिमला वृत्त के अरण्यपाल एसके शर्मा कहते हैं कि यह सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। अप्रैल-मई में गर्मी होने के कारण इन पेड़ों पर फूल नहीं निकल पाए थे। दूसरी ओर बागवानी विशेषज्ञ डा. एसपी भारद्वाज कहते हैं कि फूल आना पेड़ की स्वाभाविक प्रक्रिया है। मौसम परिवर्तन होने के कारण फूल एक-दो माह भी आते हैं। इस समय तापमान ज्यादा है। इसलिए जिन पेड़ों पर फूल नहीं खिल पाए थे वे अब खिल रहे हैं।

दैनिक जारगण, 22 जून, 2010

'System in place for controlling and preventing forest fires'

The forest and fire services departments of Himachal Pradesh have overhauled their infrastructure for control and prevention of forest fires during summers. The two departments have set up a quick response task force in at least 27 forest divisions to specifically control forest fires during the next three months.

On the lines of Chhattisgarh, Himachal is also planning to put in place a fire alert messaging system, which works in signals through the satellite network. The system is likely to be set up by the forest department. Additional Director General of Police, Fire Services and Home Guards, B. Kamal Kumar said, "After the fire services department took up the matter with principal secretary (Home), 10 home guards were deputed in each forest division. They will get one van each and will exclusively cater to prevention of forest fire incidents with locals".

The Indian Express, April 24, 2010

....

GPS to track forest fires soon

Summer Toll 499 fires, 5,653 hectare ravaged; loss : Rs. 60.53 lakh

Like in the past, this year too, forest property worth lakhs has been destroyed in fires even as the summer has just set in.

An estimated 500 fires were reported by May 5.

The raging fires swallowed up 5,653 hectares (56.53 sq km) forests across the state, as per forest department records.

Of this area, 3,233 hectare is natural or regenerated forest while 926 hectare is under plantation.

"The abnormal rise in temperature and prolonged dry spell have brought on this alarming rise in forest fires. Forest wealth worth Rs. 60,53,056 was destroyed in 499 fire incidents till May 5," said Avtar Singh, Chief Conservator (Forest Protection and Fire Control).

In 2009-10, 1,906 fire incidents burnt down 24,849 hectares forestland.

Singh said Bilaspur, Una, Hamirpur, Kangra, Sirmaur, Solan, Mandi and Shimla re the worst affected districts.

With 98 cases of forest fires, Shimla circle tops this summer's list while Nahan circle is second with 85. In Mandi and Bilaspur, 70 and 65 forest fire incidents were witnessed till Wednesday.

Forest department records say that 22 per cent or 8,267 sq km of the total forest area in the state is fire-prone. The majority fires are reported in pine forests as pine needles, rich in turpentine oil, are highly inflammable. The pine forest is found up to an altitude of 5,500 feet.

Principal Chief Conservator of Forests Vinay Tandon said that the government was developing a mechanism to collect pine needles by involving locals.

"We plan to collect pine needles from the forests and supply these to industrial units that use them as combustible material. We have identified some end users and are negotiating with them," he said.

The department also plans to adopt the global positioning system (GPS) for reporting fire incidents.

"Madhya Pradesh has made remarkable progress in monitoring forest fires through GPS. We have requested it to develop a model for this state as well. The technology would not only help monitor forest fires but also keep track of new plantations and forest encroachments," Forest Minister J.P. Nadda stated recently.

Given the sensitivity of the situation, the forest department has cancelled the leave of employees till June 15, the peak summer season.

But, the real challenge before the forest department is that most fire incidents are deliberate acts.

"Villagers also tend to set grasslands afire to get softer grass after rain. In most cases, fire from the grasslands, spreads to nearby forests," said a divisional forest officer.

As per the State Forest Report of 2005 published by the Forest Survey of India, Himachal Pradesh has 14,752 sq km of forest cover, out of which 1,097 sq km is very dense.

Hindustan Times, May 07, 2010

....

Satellite-based system to control forest fires

With a satellite-based fire alert messaging system likely to be in place by next year, the forest department hopes to further bring down incidents of forest fire and, more importantly, the devastation caused by it. Even though

incidents of fire has been much less as compared to last year, the modern technology adopted by authorities could go a long way in dealing with the problem.

With exact location of the fire and accurate information being received through satellite, the response time will be reduced to a few units.

"We have been able to achieve considerable control over fires this summer mainly due to the fact that we have a ready data base of the names of owners of grazing lands (ghasnis), whom we can alert the minute any information about a fire is received," said Avtar Singh, Chief Conservator (fire protection) at Bilaspur.

He said with the forest department having a proper database about the owners of grazing pasture, it was much easier and systematic to get controlled firing done during the winter months.

"Since all owners were asked to undertake controlled burning in the presence of the forest department staff, there was less accumulation of pine needles, leading to less forest fires," he said.

It was following major devastation caused by fires during the past few years that the state decided to adopt the model being followed by the Madhya Pradesh government, using satellite imagery-based fire alert system.

So far, a total of 699 fires have been reported from all over the state involving 6,685.24 hectares of land. The estimated loss on account of these fires is Rs. 72.29 lakh. Most of these fires are ground fires, which have not damaged the crown of the trees. Last year there were a total of 1,906 fires, which is the highest number till date with the damage being to the tune of Rs. 2.55 crore.

The Tribune, 2 June, 2010

Hydro-Electric Projects, CAT Plans and Dams etc.

लारजी में तैनात होगी ईको फोर्स

170 जवान पांच साल तक देंगे सेवाएं, नियम-शर्तें तय

सतलुज बेसिन के बाद ब्यास रिवर बेसिन पर वन विभाग नई ईको बटालियन तैनात करेगा। इसके गठन की सभी तैयारियों कर ली हैं। विभाग और बटालियन के अधिकारियों ने बैठक कर नियम और शर्तें भी तय कर ली हैं। लारजी परियोजना क्षेत्र में तैनात होने वाली यह ईको टास्क फोर्स पांच साल तक वहां काम करेगी। ब्यास बेसिन पर दूसरी ईको फोर्स पहले चरण में लारजी परियोजना क्षेत्र में काम करेगी। यहां जलोगी के पास इस बटालियन की कैंप साइट होगी। इसमें करीब 170 जवानों को तैनाती दी जा रही है, जिसका पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। कैट प्लान के धन से यह खर्च होगा और यह बटालियन काम भी कैट प्लान के तहत ही करेगी। बताया जाता है कि दूसरी बटालियन को काम सौंपने से पहले इसके लिए तय नियम और शर्तों पर पुरी बातचीत हो गई है। वन विभाग के अधिकारियों के साथ शनिवार को इससे संबंधित एक बैठक हुई, जिसमें बटालियन के लोग भी मौजूद थे। इन्हें पांच साल तक वहां काम करने को कहा गया है। इनका काम ब्यास बेसिन पर विभिन्न बिजली परियोजना के प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण का रहेगा। पहली ईको टास्क फोर्स सतलुज बेसिन पर बीबीएमबी परियोजना क्षेत्र में काम कर रही है। तत्तापानी में इस फोर्स को काम करते हुए करीब तीन साल होने को हैं। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक उनके काम की समीक्षा की गई है, जिसके परिणाम भी सुखद हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल जेएस वालिया ने कहा कि नई ईको बटालियन गठित कर दी है, जो जून से कैट प्लान के तहत काम करेगी।

दिव्य हिमाचल, 31 मई, 2010

Medicinal Plants

ढाल बनेगा रखाल

शोध में ब्रेस्ट कैंसर व क्षय रोक ठीक होने का दावा

रखाल से बनी चाय पीने वाली महिलाओं में रोग न के बराबर

ब्रेस्ट कैंसर और क्षय रोग (टीबी) से पीड़ित लोगों के लिए अच्छी खबर है। नए शोध में औषधीय पौधा रखाल इन रोगों के इलाज में रामबाण साबित हुआ है। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान मौहल (कुल्लू) के वैज्ञानिकों का दावा है कि रखाल के पत्ते के सेवन से ब्रेस्ट कैंसर ठीक होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार लाहुल-स्पीति, पांगी, किलाड़ व किन्नौर में सर्दियों में रखाल के पत्तों से बनी चाय पीने का रिवाज है।

शोध में पाया गया है कि

जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर अन्य शहरी महिलाओं के मुकाबले न के बराबर है। वैज्ञानिकों के अनुसार रखाल के पौधे के पत्ते को सुखाने के बाद अच्छी तरह पीस कर इसका चूर्ण बोतल में डाल दें। उक्त बीमारी से ग्रस्त महिलाएं चाय बनाते समय इस चूर्ण का प्रयोग बतौर पत्ती कर सकती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार कबायली क्षेत्रों में रखाल के पत्ते से नमकीन चाय भी तैयार की जाती है। वहीं, रखाल के पौधे का व्यवसायिक महत्व भी है। इसकी लकड़ी से फलोरिंग की जाती है। इससे फर्नीचर भी तैयार किया जाता है तो मजबूत होने के साथ-साथ सदियों तक खराब नहीं होता है। रखाल की लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। पेंसिल तैयार करने में भी रखाल की लकड़ी प्रयोग की जाती है।

छह मीटर लंबा पौधा

हिमालय में 1800 से 3300 मीटर की ऊंचाई पर छायादार क्षेत्र में उगने वाला करीब छह मीटर लंबा औषधीय पौधा रखाल (कोनीफेरस, हिमालयन यू) हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और मेघालय में भी पाया जाता है। हिमाचल में यह पौधा शिमला, कमरूनाग, शिकारी देवी, खजियार, जगतसुख, हामटा, बंजार, मनाली, लगवैली, काइस और सोलंग वैली में पाया जाता है।

सिर दर्द, रक्तचाप व डायरिया के उपचार में भी कारगर

जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एसएस सामंत का दावा है कि रखाल का पौधा ब्रेस्ट कैंसर व क्षयरोग (टीबी) क`उपचार में कारगर है। इसके अलावा सिर दर्द, रक्तचाप व डायरिया के उपचार में भी रखाल कारगर साबित हुआ है। उनका दावा है कि इस पोधे को हिंदुस्तान के किसी कोने में उगाया जा सकता है। इसे उगाने में तापमान को नियंत्रित करने के लिए पालीहाउस की मदद ली जा सकती है। रखाल के पौधे को लोकप्रिय बनाने के लिए संस्थान में दो हजार पौधे लगाए गए हैं। संस्थान द्वारा घाटी के किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि वे घरों में इन पौधों को लगा कर इसका लाभ उठाएं। इससे किसान अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर सकते हैं। संस्थान में इसके इलावा भी विभिन्न प्रजातियों के पौधों पर शोध किया जा रहा है। इन पौधों को विदेश में भी भिजवाया जाता है।

दैनिक जागरण, 2 अप्रैल, 2010

....

जंगली अनार से तैयार किए जाएंगे हेल्थ ड्रिंक

नौणी हार्वेस्ट विभाग ने विभिन्न उत्पाद बनाने की तकनीक विकसति की

प्रदेश के जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले जंगली अनार (दाडू) से अब स्वास्थ्यवर्द्धक पेय पदार्थ, स्क्वेश, जैली व सीरप बन सकेंगे। इस पर लघु औद्योगिक इकाई स्थापित कर लोग अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सकेंगे। डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौणी के पोस्ट हार्वेस्ट विभाग ने जंगली अनार से विभिन्न उत्पाद बनाने की तकनीक विकसति की है। शीघ्र ही यह तकनीक किसानों को हस्तांतरित की जाती है।

सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू व चंबा जिला में जंगली अनार प्रचूर मात्रा में मिलता है। लोग जुलाई व अगस्त माह में जंगलों व अनार को एकत्र करके सूखाते हैं। इसके बाद इसे बाज़ार में बेचा जाता है।

पॉलीथिन ड्रायर तैयार

डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नौणी के पोस्ट हार्वेस्ट विभाग के वैज्ञानिक डॉ. एनएस ठाकुर ने जंगली अनार की ड्राइंग तैयार की है। उन्हांने बताया कि पारंपरिक तरीके से अनार निकालने के कारण इसके दाने काले पड़ने लगते हैं। इसके लिए इसे प्री ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि अनार का दाना सूखने के बाद भी काला न पड़े।

इसके अलावा अनारदाना को सूखाने के लिए उन्होंने पॉलीथिन ड्रायर बनाया है। ड्रायर सस्ता होने के कारण आम आदमी की पहुंच में है। डॉ. ठाकुर ने बताया कि कई किसान अनारदाना को सूखाकर उसे बोरियों में भर देते हैं, जिससे इसे नमी आ जाने के कारण कई बार अनारदाना खराब हो जाएगा। उन्होंने बताया कि विभगा जागरूकता शिविरों का आयोजन कर, किसानों को जंगली अनार के रखरखाव की तकनीकी जारकारी देंगे।

दैनिक भास्कर, 6 अप्रैल, 2010

....

आम आदमी की पहुंच से दूर गुच्छी

कम पैदावार-बढ़ती कीमतों ने किया निराश

चैऊं (गुच्छी) के नाम से अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में विख्यात देवभूमि के जंगल में प्राकृतिक रूप से उगने वाली गुच्छियां आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं।

कम पैदावार के चलते इस वर्ष भी इनकी कीमत चार हज़ार से लेकर आठ हज़ार तक आंकी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में इसकी कीमत अच्छी मिलती है। लोग इससे काफी मुनाफा कमाते हैं। देवभूमि के जंगलों में बादलों की गर्जन के साथ

प्राकृतिक रूप से उगने वाली गुच्छियों को अभी तक वैज्ञानिक तरीके से तैयार करने में सफलता नहीं मिली है। प्रदेश भर में गुच्छियों की करीब आठ किस्में पाई जाती हैं।

इसमें काले रंग की गुच्छी को सर्वोत्तम माना गया है। काले रंग की गुच्छियां फरवरी से लेकर अप्रैल तक बादलों की गर्जन के साथ प्राकृतिक रूप से बाहर निकलती हैं, जबकि पीले रंग की गुच्छियां सितंबर-अक्तूबर के महीने में पाई जाती हैं। सबसे अधिक मांग बाज़ार में काली गुच्छियों की रहती है। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में अधिकतर ग्रामीण सपरिवार जंगलों में सुबह से ही गुच्छियों की तलाश में निकल जाते हैं। सैंकड़ों ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन गुच्छियां ही हैं। जंगल के करीब रहने वाले परिवार सीजन में औसतन गुच्छियों से दस से 20 हज़ार तक की कमाई कर लेते हैं। मार्च के शुरू में सीजन के चलते गुच्छियों के दाम 1500 से 2500 रुपए तक रहते हैं, जबकि इस वर्ष कम पैदावार के चलते गुच्छियों के दामों में सात हज़ार से ऊपर की बढ़ोतरी हुई है। जानकारों के अनुसार गुच्छियां शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा, लाहुल-स्पीति आदि जिलों में पाई जाती हैं। स्वाद और औषधीय गुणों के कारण पांच सितारा होटलों में इसकी प्लेट 700 तक बेची जाती है, तो वहीं विशेषज्ञ के अनुसर अब गुच्छी का प्रयोग दवा के निर्माण फ्लेवर बनाने के लिए भी किया जा रहा है।

शिमला में गुच्छियों की कीमत चार हज़ार से सात हज़ार तक है, जबकि अन्य राज्य में इस वर्ष गुच्छी के दाम 12000 तक हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर में गुच्दियों की कीमत का अनुमान यहां के दामों को देखकर ही लगाया जाता है। गुच्छी की परख रखने वाले स्थानीय व्यापारियों के अनुसार इस वर्ष कम पैदावार के चलते गुच्छियां मंडी मं कम आ रही हैं।

दिव्य हिमाचल, 17 अप्रैल, 2010

....

कैंसर की रोकथाम को वनकाकड़ी रामबाण!

हिमाचल के ठंडे इलाके में पाया जाता है यह पौधा

कैंसर की रोकथाम के लिए वनकाकड़ी रामबाण का काम करती है। यह खुलासा हिमाचलय जैव संपदा एवं प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के विषयवाद विशेषज्ञों के शोध में हुआ है। विशेषज्ञों का दावा है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला की पांगी-भरमौर की पहाड़ियों सहित निचले इलाकों में भी जड़ी-बूटियों का भंडार मौजूद है। बस, इन बेशकीमती पौधों को जानने व समझने भर की देर है। हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान के विशेषज्ञ डॉ. अनिल सूद एवं डॉ. राकेश डियो सिंह ने दावा किया कि वनकाकड़ी मेडिसन प्लांट का एक विशेष अंग है, जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों को मात देता है। इनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला के पांगी तथा भरमौर के लोग वनकाकड़ी की खेती कर आमदनी का साधन बना सकते हैं। प्रौद्योगिकी संस्थान के सामान्य बायोटेक्नोलॉजी विशेषज्ञ डॉ. अनिल सूद ने बताया कि इस बार लाहौल स्पीति जिला में हाई अल्टीट्यूड लैब का निर्माण किया जा रहा है। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने दो करोड़ की धनराशि की स्वीकृति दे दी है। प्रयोगशाला के स्थापित होते ही यहां पर पिछले कई वर्ष से लुप्त हो रही इन वनस्पतियों पर शोध होगा। उन्होंने बताया कि लाहौल-स्पीति और पांगी घाटी में कड़ु, पतीश, पंजा, काला जीरा, सालमपंजा और वनकाकड़ी का खजाना भरा पड़ा है। लोगों को इसके महत्त्व जानने की ज़रूरत है।

अमर उजाला, 18 अप्रैल, 2010

....

लोगों से प्लास्टिक कचरा खरीदेगी सरकार

हरित पत्रकारिता पुरस्कार मिलेगा

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि राज्य सरकार आम जनता से 3 रुपए प्रति किलो की दर से प्लास्टिक का कचरा खरीदेगी, जो सड़क निर्माण में प्रयोग में लाया जाएगा। यह कचरा नगर एवं शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से खरीदा जाएगा जिसकी एवज में इन निकायों को एक रुपया प्रति किलो की दर से 'हैंडलिंग चार्ज' दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश एशिया उप महाद्वीप का पहला राज्य होगा। उन्होंने प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों पर आधारित रिपोर्टिंग के लिए 'हरित पत्रकारिता पुरस्कार' प्रदान करने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री आज शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय पृथ्वी दिवस समारोह और पॉलीथीन हटाओ - पर्यावरण बचाओ अभियान के द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर बोल रहे थे। यह अभियान 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि वे हिमाचल प्रदेश को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल राज्य बनाने में सहयोग दें और पर्यावरण विरोधी गतिविधियों के मामले में जीरो टॉलरैंस की नीति अपनाएं। उन्होंने कहा कि राज्य के

लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण के कार्य में प्लास्टिक के कचरे का सफलतापूर्वक प्रायोगिक आधार पर उपयोग किया है जिसके रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती और यह सड़क लंबे समय तक प्रयोग में लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर तक खुले में शौचमुक्त का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्रदान करने की पहल की है। इसी प्रकार ऐसी ग्राम पंयाचतों और स्थानीय शहरी निकायों जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, को भी पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो प्लास्टिक कचरा इकट्ठा कर ऐसी चिन्हित स्थानीय एजैंसियों को बेचेंगे जहां से इसका उपयोग लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण में सुनिश्चित बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसकी कीमत 3 रुपए प्रति किलोग्राम होगी जबकि ग्राम पंचायतों व शहरी निकायों को इसके हैंडलिंग चार्ज के लिए एक रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाएगा। प्रो. धूमल ने कहा कि प्रदेश सरकार सभी जिला मुख्यालयों पर कागज पुनर्चक्रण इकाइयां स्थापित करेगी जिनमें कार्यालयों के उपयोग के लिए बेकार कागजों को पुनर्चक्रित कर हस्त निर्मित फाइलें व लेखन सामग्री तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब यह निर्णय लिया गया है कि सभी जिला मुख्यालयों में चरणबद्ध तरीके से ये इकाइयां स्थापित की जाएं, ताकि कार्यालयों के इर्द-गिर्द कचरा बिखरा न रहे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण विभाग 'करने और न करने संबंधी' सूचना के पर्चे छपवा कर लोगों में तथा यहां आने वाले पर्यटकों को वितरित करेगा ताकि प्रदेश में आने वाले सभी आगंतुक भी पर्यावरण संरक्षण के विषय में सचेत रहें। यह पर्चे प्रत्येक शिक्षण संस्थान में भी वितरित किए जाएंगे और बच्चों को प्रात:कालीन प्रार्थना के समय इस संबंध में याद दिलाया जाएगा।

होटलों को भी प्रेरित किया जाएगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि होटलों को भी पर्यावरण मित्र अधोसंरचना सुविधाएं अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तम्बाकू खाने के आदी व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी न डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा और उन्हें इन आदतों को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने प्लास्टिक पर लगाए गए प्रतिबंध को सफल बनाने के लिए जनता व व्यवसायिओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे जनता का समर्थन प्राप्त न हो। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वे राज्य में हरित आवरण बढ़ाने में सहयोग दें और बूढ़े तथा मृत पेड़ों के स्थान पर नया पौधरोपण करें। उन्होंने कहा कि पानी बेशकीमती है और भविष्य तथा वर्तमान के लिए पानी का संरक्षण आवश्यक है। उपायुक्त शिमला जे. एस.राणा, उपायुक्त कांगड़ा आर.एस.गुप्ता, निदेशक शहरी एवं स्थानीय निकाय रजनीश कुमार, प्रधान मुख्य अरण्यपाल डॉ. पंकज खुल्लर, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, डीयर पार्क व बीड़ जिला कांगड़ा नामक स्वयंसेवी संस्था के प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर पर्यावरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों और उनके द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों पर प्रस्तुतिकरण दिया।

पंजाब केसरी, 23 अप्रैल, 2010

जड़ी-बूटी उगाना सीखेंगे किसान

5 करोड़ की राशि से विकसित होगा माइक्रोप्रोपोगेशन रिसर्च सेंटर

जोगिन्द्रनगर (माइक्रोप्रोपोगेशन) अनुसंधान संस्थान में किसान जड़ी-बूटी उगाने का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस माह सरकार ने इस संस्थान में जड़ी-बूटी संरक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। हाल ही में आयुर्वेद विभाग की विशेष टीम में यहां स्थापित होने वाले हार्ड चैंबर को स्थापित करने और विशेषज्ञों की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। डेढ़ माह अनुसंधान केन्द्र में किसानों का प्रशिक्षण कोर्स व अन्य अध्ययन शुरू हो जाएगा।

करोड़ों का मिला बजट

केन्द्र सरकार ने इस केन्द्र को विकसित करने के लिए 5 करोड़ रूपए की राशि प्रदान की है। जिसकी मदद से इस संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्रव्य गुण में विकसित किया जा रहा है। जो प्रदेश में औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देगा। यहीं नहीं विलुप्त होती जा रही औषधीय का शोध व संरक्षण भी किया जा सकेगा। जैसे की सुगंधबाला, सर्पगंधा, वनककड़ी, अतीस पतीस व जटामांसी आदि बूटियों की नर्सरी उगाई जा सकेगी।

फार्मा कंपनियों पर निर्भरता

अभी प्रदेश में प्राकृतिक तौर पर उगने वाली बहुमूल्य औषधीय पौधों पर ही आयुर्वेद फार्मा कंपनियां निर्भर है। हर साल बहुतायत में जंगलों से बहुमूल्य औषधीय पौधों का दोहन हो रहा है। जिससे कई औषधीयां खत्म होने की कगार पर है।

दैनिक भास्कर, 28 जून, 2010

बांस की पैदावार भरेगी किसानों की जेब

करसोग में सम्मेलन पर मुख्य अरण्यपाल की सीख

प्रदेश के हरे-भरे जंगलों को बचाने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। किसानों द्वारा अपने क्षेत्रों में पौधारोपण करते हुए जंगलों को बढ़ावा तथा आर्थिक मजबूती भी प्राप्त की जा सकती है। यह बात करसोग वन मंडल के सभागार में मड़ी वृत्त स्तर के वन अधिकारियों, कर्मचारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में रविवार को प्रदेश मुख्य अरण्यपाल जीएस गुराया ने बतौर मुख्यातिथि कही। इस अवसर पर वन अरण्यपाल मंडी बीडी सुयाल, वन मंडलाधिकारी करसोग, एचके सरवटा, वन परिक्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा, हीरा खाची तथा मंडी वृत्त से आए वन अधिकारियों ने चंद्र शील शर्मा, नरेंद्र चंदेल, पर्यावरण प्रेमी नेक राम शर्मा व खंड करसोग से लगभग एक दर्जन संयुक्त वन प्रंबधन समितियों के दर्जनों सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यातिथि ने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया गया है, जिसमें बांस की पैदावार से प्रदेश का पैसा प्रदेश में ही रह सकता है व अनेकों महत्त्वपूर्ण विकास कार्यों में भी बांस को उपयोग में लाया जा सकता है।

दिव्य हिमाचल, 26 अप्रैल, 2010

....

बांस की पैदावार भरेगी किसानों की जेब

करसोग में सम्मेलन पर मुख्य अरण्यपाल की सीख

प्रदेश के हरे-भरे जंगलों को बचाने के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। किसानों द्वारा अपने क्षेत्रों में पौधारोपण करते हुए जंगलों को बढ़ावा तथा आर्थिक मजबूती भी प्राप्त की जा सकती है। यह बात करसोग वन मंडल के सभागार में मंडी वृत्त स्तर के वन अधिकारियों, कर्मचारियों के दो दिवसीय सम्मेलन में रविवार को प्रदेश मुख्य अरण्यपाल जीएस गुराया ने बतौर मुख्यातिथि कही। इस अवसर पर वन अरण्यपाल मंडी बीडी सुयाल, वन मंडलाधिकारी करसोग, एचकेसरवटा, वन परिक्षेत्र अधिकारी ओम प्रकाश शर्मा, हीरा खाची तथा मंडी वृत्त से आए वन अधिकारियों ने चंद्र शील शर्मा, नरेंद्र चंदेल, पर्यावरण प्रेमी नेक राम शर्मा व खंड करसोग से लगभग एक दर्जन संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के दर्जनों सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यातिथि ने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन चलाया गया है, जिसमें बांस की पैदावार से प्रदेश का पैसा प्रदेश में ही रह सकता है व अनेकों महत्त्वपूर्ण विकास कार्यों में भी बांस को उपयोग में लाया जा सकता है।

दिव्य हिमाचल, 26 अप्रैल, 2010

....

वनों से सूखी लकड़ी ले जा सकेंगे लोग

परंपरागत वन अधिकारों पर पाबंदी हटाई

टिंबर डिस्ट्रीब्यूशन (टीडी) की आड़ में परंपरागत वन अधिकारों पर लगाई गई अघोषित पाबंदी वन विभाग ने हटा ली है। अब किसान वनों से चारा और ईंधन के लिए सूखी लकड़ी लाने के हकदार हो गए हैं। वन विभाग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) को लिखे एक पत्र में इसका खुलासा किया है। किसानों के ही संगठन किसान सभा ने सरकार से परंपरागत वन अधिकारों को बहाल करने की मांग की थी। मालूम हो कि संगठन ने इनकी बहाली और टीडी नियमों की खामियों को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन भी चलाया।

पत्र में स्वीकार किया गया है कि वनों से ईंधन, चारे एवं अन्य उत्पादों के बारे में बर्तनदारों के हक हकूकों पर नए टीडी नियमों का कोई प्रभाव नहीं है। और ये पहले की ही तरह जारी रहेंगे। कोर्ट के निर्देश पर टीडी अधिकार तो बहाल हो गए, पर अन्य वन अधिकारों को लेकर विभाग ने कोई भी निर्देश फील्ड स्टाफ को नहीं दिए। विभाग के अधिकारी भी ये मानते हैं कि अन्य वन अधिकारों पर मौखिक रूप से ही पाबंदी थी, लेकिन लिखित में कोई निर्देश न तो बहाली के थे और न ही बंद करने के। इससे किसानों को काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा था। अब सरकार ने निजी भूमि से भी पेड़ काटने की इजाज़त दे रखी है। मगर दो पेड़ से ज्यादा कोई भी किसान घरेलू इस्तेमाल के लिए पेड़ नहीं काट

सकेगा। दो से अधिक पेड़ों को काटने के लिए उसे डीएफओ से अनुमति लेनी होगी। किसान के प्रदेशाध्यक्ष और सेवानिवृत्त अरण्यपाल डॉ. कुलदीप तंवर का कहना है कि वन विभाग ने परंपरागत वन अधिकारों पर प्रैक्टिस में प्रतिबंध लगाया है। करीब ढाई साल से यह प्रतिबंध टीडी के साथ ही जारी रहा। डॉ. तंवर के अनुसार किसानों और वन अधिकारियों के बीच कम्यनिकेशन गैप की वजह से समस्या आ रही है, अफसरों को चाहिए कि वे इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें।

दैनिक भास्कर, 19 मई, 2010

....

Policy/Law

दरवाजे, खिड़कियां बनाएगा वन निगम

राज्य वन निगम ने आय बढ़ाने के लिए लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियां बनाने की यूनिट लगाने का फैसला लिया है। निगम प्रबंधन इस यूनिट को कुल्लू के शमशी में स्थापित करेगा। इसे ज्वाइनिंग यूनिट के नाम से खोला जाना प्रस्तावित है।

निगम प्रबंधन का मानना है कि पेड़ों को स्लीपर में बदलते समय काफी वेस्ट लकड़ी बच जाती है। इसका इस्तेमाल दरवाजे, खिड़कियों के इस्तेमाल के लिए किया जाएगा। शमशी में इसका निर्माण कर निगम के हर डिपो में इसे उपलब्ध करवाने की योजना है। निगम प्रबंधन को इससे सालाना करोड़ों की आय होने की संभावना है। राज्य वन निगम के प्रबंध निदेशक आरके गुप्ता ने इसकी पुष्टि की है।

गुप्ता ने बताया कि अगले वित्तीय वर्ष से निगम के डिपुओं में इसे उपलब्ध करवाने की दिशा में काम शुरू हो गया है। इसकी दरें निजी डिपुओं से कम रखे जाने के लिए काम किया जा रहा हैं दरें तय करने के लिए निगम प्रबंधन ने कमेटी का गठन किया है।

अमर उजाला, 20 अप्रैल, 2010

....

Waste plastic now has a price in HP

Dhumal govt starts second phase of 'say-no-to-polythene' campaign, to buy back waster plastic bags from public and use them in construction of roads

Adding a value to waste polythenes- the biggest source of pollution in the hills and urban towns - Himachal Pradesh launched an innovative scheme on Thursday to buy back plastic waste from the public for its use in the construction of roads.

Himachal is the first state in the country, and perhaps in Asia, to start this scheme. The plastic will be bought at Rs. 3 per kg.

The local urban bodies and other government agencies, which will open collection centres shortly, will supply this plastic waste to the state's public works department (PWD). The agency will get a handling charge of Rs. 1 per kg.

In Himachal Pradesh, there has been a complete ban on polythene bags since October 2, 2009. The state has successfully introduced paper, jute and cotton bags as alternatives.

Launching Phase II of 'Plastic Hatao, Paryavaran Bachao' campaign here on Thursday, the Earth Day, Chief Minister Prem Kumar Dhumal also proposed to ban throwing of empty gutka and tobacco pouches in the open.

"This is the biggest form of plastic pollution and the collection of this waste is impossible. The government will either bringing in a suitable amendment in the law, or promulagate an ordinance to introduce on-the-spot penalty to deal with violators," he said.

The CM added : "I am directing all deputy commissioners and top enforcing agencies, including the police, to take stern action against those found throwing gutka pouches in the open. The gutka addicts will either have to give up the habit or pay fines."

The second phase of campaign will have a series of new steps. The CM proposed a 'Green Journalism Award' for media professionals writing on environmental issues and creating awareness on the polythene ban.

Hours before the function, Dhumal inaugurated a new stretch of the road to Shimla airport, which has been built using waste polythenes collected during the first phase of the campaign. Over Rs. 8.5 lakh awards were presented to best districts, urban local bodies and panchayats having done a good job in the collection of waste polythenes.

Deputy commissioners R S Gupta (Kangra) and J S Rana (Shimla), who shared a prize of rs. 1 lakh, made a presentation on the strategy they had adopted to clean the hillsides of polythenes.

Dhumal announced that the government would set up waste paper recycling units in every district head-quarter to get the official wastepaper recycled and manufacture handmade file covers and other stationery for use

in the offices. There is already one waste paper recycling unit in the HP Secretariat.

He asked the environment and pollution control department to print literature of 'do's and don'ts' for tourists entering Himachal that should be distributed at the entry points.

The chief minister said hotels and resorts would also be advised to adopt eco-friendly infrastructural facilities. There will be rating of such hotels and resort on environmental aspects.

Earlier, Chief Secretary Asha Swarup said with the urbaisation and migration of population from rural areas was resulting in an increase in the quantum of garbage.

The Indian Express, April 23, 2010

पाइन निडल उठाने की योजना को सरकार से मिली हरी झंडी

गांववासी जंगलों से चील के पाइन निडल उठा स्वयं बेच कमा सकेंगे आर्थिक लाभ

होशियारपुर की जेसीटी व ऊना का महेश उद्योग खरीदेगा पाइन निडल

जंगलों में चील के पेड़ों के पाइन निडल (पत्ते)वनों में आग लगने की घटनाओं की बढ़ौती करते हैं। जिससे नुकसान ज्यादा होता है। ऐसे में सरकार ने जंगलों से इस ज्वलन शील पाइन निडल को उठाने के लिए जिला वन विभाग द्वारा भेजी गई एक योजना सेव फोरेस्ट को हरी झंडी दी है। इस योजना से आग लगने की घटनाएं कम होंगी, वहीं स्थानीय निवासी अपनी आर्थिक ज़रूरत को भी पूरा कर पाएंगे। योजना को क्लीयर करने में वनमंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विशेष रूचि दिखाते हुए इसे लागू करवाया है। जिला ऊना की 235 पंचायतों में से करीब 145 पंचायतों के लोगों को इसका लाभ हो सकेगा। इस योजना के तहत जिला ऊना के जंगलों में चील के पाइन निडल जो भरपूर मात्रा में बेकार पड़े रहते हैं, को जंगलों से उठाकर मार्केट में बेचने का प्रावधान किया गया है। एक विभागीय अनुमान के अनुसार जिला में 18 हज़ार मिट्रिक टन पाइन निडल प्रतिवर्ष जंगलों में मिलती है। इस योजना के लागू होने से संबंधित गांव पंचायतों के लोग पाइन निडल को जंगलों से एकत्रित कर उचित दाम पर मार्केट में बेच सकेंगे और इसके लिए उन्हें वन विभाग की कानूनी दावपेंचों में उलझना भी नहीं पड़ेगा। पाइन निडल को राज्य के भीतर व बाहर बेचने के लिए अनुमति आसानी से गांव स्तर पर भी मिल सकेगी। योजना के अनुसार इस पाइन निडल को एकत्रित कर लोग ऊना के महेश उद्योग में एक रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से तथा होशियारपुर के जेसीटी उद्योग में 1.50 रुपए से 1.75 रुपए तक प्रतिकिलो बेच सकेंगे। इसकी अनुमति ग्राम पंचायत प्रधान से प्राप्त हो सकेगी। एक अनुमान के अनुसार ग्राम पंचायतों को प्रत्येक सीजन में 90 हजार रुपए की आमदन हो सकेगी। वहीं इसको बेचने वाले व्यक्ति को खर्चे निकाल 70 पेसे प्रतिकिलो का लाभ होगा। एक व्यक्ति एक दिन में पाइन निडल को एकत्रित कर 700 से 800 रुपए तक की अतिरिक्त आमदन प्राप्त कर सकता है। जंगलों में पाइन निडल एकत्रित करने से लोगों को विभाग नहीं रोकेगा तथा विभाग के गार्ड इस पर नज़र ज़रूर रखेंगे ताकि किसी प्रकार का अवैध कार्य न हो सके। वन विभाग के जिला अधिकारी आरके राज ने बताया कि राज्य सरकार के वन विभाग ने इस योजना को अनुमति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जिला के अंब व बंगाणा क्षेत्र में लोग इस का लाभ उठा सकते हैं।

अजीत समाचार, 23 अप्रैल, 2010

जिला में वनों की आग के 21 मामले हुए दर्ज

जिला वन अधिकारी आरके राज ने बताया कि जिला ऊना में अभी तक 21 आग के मामले दर्ज किए गए हैं। जिसमं 90 हज़ार रुपए का नुकसान आंका गया है। उन्होंने बताया कि 419 हेक्टेयर क्षेत्र में आग लगी है। उन्होंने कहा कि आग को रोकने के लिए 95 फायर वाचर नियुक्त किए हैं, वहीं अंब व रामगढ़धार की रेंज में आठ-आठ होम गार्ड जवानों की टुकड़ियां भी तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में पाइन निडल एकत्रित करने का कार्य किया गया था, उनमें आग की घटनाएं कम हुई हैं। उन्होंने बताया कि रामगढ़ में 11 भरवाई में तीन, अंब में चार, बंगाणा में एक व ऊना में दो मामले वनों में आग के सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग वनों में आग पर काबू पाने के लिए ठोस कार्रवाई कर रहा है।

अजीत समाचार, 23 अप्रैल, 2010

अब सीएफ फाइनल करेंगे नई सड़कों के प्रस्ताव

हर दूसरे महीने वन अरण्यापाल लेंगे एक्सईएन डीएफओ की बैठकें

हिमाचल प्रदेश में डीएफओ क बजाय अब नई सड़कों के प्रस्तावों को सीएफ ही फाइनल करेंगे। इस तरह से डीएफओ को दी गई शक्तियां एक तरह से छीन ली गई हैं। हालांकि, यह निर्णय सड़क निर्माण प्रक्रिया में लेटलतीफी को रोकने के

लिए राज्य लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की संयुक्त रूप से बैठक के बाद लिया गया है।

हर दूसरे महीने वन अरण्यपाल (सीएफ) के पास पीडब्ल्यूडी एक्सईएन और डीएफओ की बैठकें होंगी। इनमें ही नई सड़कों के प्रस्तावों को आगे प्रेषित करने अथवा नहीं करने का फैसला लिया जाएगा।

हिमाचल में सड़को के निर्माण की प्रक्रिया शुरुआत से ही ढीले तरीके से चलती रही है। यानी किसी भी नई सड़क के निर्माण के लिए जब पीडब्ल्यूडी एक्सईएन द्वारा कोई प्रस्ताव बनाया जाता है, तो इसमें डीएफओ की रिपोर्ट का संलग्न होना ज़रूरी होता है। डीएफओ ही यह तय करते हैं कि संबंधित क्षेत्र में कितना वन क्षेत्र है और वहां सड़कें बनाने में वन भूमि से संबंधी क्या अड़चनें हैं? इससे पूर्व डीएफओ द्वारा बनाई गई फाइनल रिपोर्ट को ही उच्च अधिकारी सरकार के ध्यानार्थ भेजते रहे हैं। आमतौर पर डीएफओ स्तर पर ही सड़क के प्रस्ताव आगे भेजने में देरी होती रही है। इसकी पूरी स्क्रीनिंग भी नहीं हो पाती है। राज्य लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता नंदलाल शर्मा ने पुष्टि की कि दोनों विभागों ने यह तय किया है कि अब डीएफओ के फाइनल करने से ही सड़कों के मामले आगे नहीं जाएंगे। हर दूसरे महीने सीएफ के पास बैठकों में ही सड़कों के प्रस्तावों पर हर पहलू से अध्ययन किया जाएगा और इन्हें आगे भेजा जाएगा। इससे सड़क निर्माण प्रक्रिया अविलंब चलती रहेगी।

अमर उजाला, 27 अप्रैल, 2010

....

Ex-servicemen roped in for a greener Bilaspur

Part of forest protection force, they will raise 'Sainik vans' to enhance forest cover, will plant 3,200 saplings this year

With the active involvement of ex-servicemen, the Bilaspur forest division has set up a Forest Protection Force (FPF) on the lines of the Eco Task Force to enhance the forest cover.

The FPF, comprising 68 members, will be on the job from Wednesday.

The FPF will raise 'sainik vans', which will be protected by ex-servicemen in association with forest officials.

These 'sainik van' will be named after soldiers from the district who have made the supreme sacrifice for the nation.

The FPF will be planting 3,200 saplings this year in three Sainik Vans at Kalol, Fatoh and Doli-Kallan, which will be named after Param Vir Chakra awardee Havaldar Sanajy Kumar, Second Lt. Tek Singh Chandel, who was killed in the 1962 war with China and Naik Ashwani Kumar, recipient of a Sena medal, respectively. Most of the vegetation in these 'sainik vans' will act as a source of fodder, fuel wood and timber to help villagers meet their requirements.

District Forest Officer Pushpinder Rana said this pilot project was aimed at enhancing the green cover, ensuring better coordination among ex-servicemen and local field staff and benefitting ex-servicemen and their families.

Rana said the FPF would also help in checking fire incidents by providing information to forest officials so that the response time in dealing with fires could be reduced.

"This way, locals can be better mobilised to bring forest fires under control," he said.

The DFO said a district level committee of the FPF would meet once in three months to discuss new proposals and analyse the work done during the previous quarter. Similarly, range-level committees of the FPF will also meet every three months.

Hindustan Times, April 29, 2010

....

कोटखाई की जनता का हक कटा

दस वर्ष तक लकड़ी नहीं काट पाएंगे नागरिक, कर्मचारियों का होगा तबादला

राज्य वन विभाग ने अवैध कटान पर गंभीरता दिखाते हुए कर्मचारियों और बर्तनदारों पर कार्रवाई करने का फैसला लिया है। विभाग ने बर्तनदारों के वन अधिकारों पर दस साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही जंगलों में तैनात वन कर्मियों के तबादले की सूची भी तैयार कर ली है।

वन महकमे ने कोटखाई रेंज के गवाच, कलबोग और ओढ़ी जंगलों मे अवैध कटान का बड़ा मामला सामने आने के बाद यह कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। विभाग और विजिलेंस की टीम को यहां से 2200 छोटे बड़े स्लीपर बरामद कर चुकी है। बाज़ार में इनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। विभाग को आशंका है कि यह कटान लंबे समय से चल रहा है। इसके पीछे कुछ स्थानीय लोग भी शामिल हैं। वन कर्मियों पर जंगल में न जाने के मामले पर कार्रवाई होगी। विभाग ने अधिकतर स्लीपर जंगलों के बजाए नालों से बरामद किए हैं। छापेमारी के शुरूआत के दौरान बरामद किए गए स्लीपर ताजा तथा बाद में बरामद हुए लकड़ी के नग पुराने बताए जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि लोग मामले की जांच शुरू होने के बाद अपने कब्जे में रखे स्लीपरों को रात को नालों में

फेंक रहे हैं। इसलिए बर्तनदारों पर कार्रवाई की जा रही है। लंबे समय तक कटान की सूचना न मिलने से कर्मियों के तबादले भी तय हैं। इसमें करीब 25 कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। वन महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय शुक्ला ने माना कि इन तीनों जंगलों के बर्तनदारों के वन अधिकार दस साल के लिए मंगलवार से बंद कर दिए जाएंगे। फील्ड में न जाने और विभाग को सूचना न देने पर कर्मचारियों के तबादले भी होंगे। जांच में दोषी पर कार्रवाई होगी।

अमर उजाला, 18 मई, 2010

Wildlife Conservation

लो! कैमरे की क्लिक पर तेंदुए

वन विभाग ने किब्बर में लगाए कैमरे, स्नो लैपर्ड में हिमाचल की स्थिति बेहतर

राज्य पक्षी जुजुराना के संरक्षण पर खर्च होंगे डेढ़ करोड़

प्रदेश में तेंदुओं की स्थिति पता लगाने के लिए वन विभाग का वन्य प्राणी विंग कैमरा ट्रैप सर्वे करेगा। राज्य पक्षी जुजुराना के संरक्षण क लिए रामपुर के सराहन स्थित पार्क पर डेढ़ करोड़ खर्च किए जाएंगे। यहां जुजुराना की ब्रीडिंग की जाती है, जिन्हें बाद में जंगलों में छोड़ दिया जाता है।

प्रदेश में वन्य जीवों को सही स्थिति का आंकड़ा जानने के लिए वन विभाग प्रयास कर रहा है। 2004 की गणना में प्रदेश में तेंदुओं की संख्या 760 थी। यह कहना अभी उचित नहीं होगा यहां तेंदुओं की संख्या बढ़ रही है या घट रही है। विभाग कैमरे के माध्यम से इनकी गणना शुरू करेगा। इस कैमरे की बैटरी लगभग 20 से 25 दिन तक चल जाती है। कैमरे में सभी प्रकार के जंगली प्राणी कैद हो जाते हैं। स्नो लैपर्ड की गणना के लिए जनजातीय क्षेत्र किन्नौर के किब्बर में कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। बर्फानी तेंदुओं की स्थिति संतोषजनक है। अंतरराष्ट्रीय मानक स्तर पर यदि 100 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत बर्फानी तेंदुए की संख्या 4-5 है तो स्थिति बेहतर है। राज्य पक्षी जुजुराना के संरक्षण के लिए वन्य प्राणी विंग प्रयास कर रहा है। जुजुराना हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और पाकिस्तान पाया जाता है। हिमाचल में जुजुराना की स्थिति बेहतर है। यहां प्रति डेढ़ वर्ग किलोमीटर में एक जुजुराना दिखाई देता है। जुजुराना हिमाचल के रामपुर बुशहर, कुल्लू, हिमालयन नेशनल पार्क, चंबा, धौलाधार में इसकी संख्या अच्छी है। इसके अलावा चेहड़ जिसे स्थानीय भाषा में घासनी का मुर्गा कहते हैं उसके संरक्षण के लिए वन विभाग चाइल में वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी का निर्माण किया है। यह परिंदा खासकर उन क्षेत्रों में मिलता है जहां घास अच्छी मात्रा में होता है। वन विभाग के मुख्य वन्य अरण्यपाल संजीवा कहते हैं कि पौंग डैम में पर्यावरण शुद्ध होने के कारण अधिकतर पक्षी यहां का रुख कर रहे हैं। यहां करीब डेढ़ लाख परिंदे इस सर्दियों में दिखाई दिए। यह परिंदे साइबेरिया, मंगोलिया और सेंट्रल एशिया से यहां आ रहे हैं।

वन्य प्राणी शहरों में नहीं, लोग जा रहे हैं जंगलों में

वन्य प्राणी विंग के मुख्य अरण्यपाल संजीवा पांडे कहते हैं कि जंगलों में लोगों ने घर बना लिए हैं। मनुष्य जंगलों की ओर जा रहा है, जंगल घट रहे हैं, वहां जंगली जानवरों के खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि लोग जंगलों की ओर जा रहे हैं न कि वन्य जीव आबादी की ओर रहे हैं।

जागरुकता ज़रूरी

कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब वन्य जीव शहर में आ जाता है। ऐसे में उन्हें वापस जंगल मं जाने के लिए एक ही उपाय है कि लोग इसके बारे में जागरूक हों। ऐसे अवसर पर लोगों को तेंदुए के समीप एकत्रित नहीं होना चाहिए। ऐसे में वह आक्रामक हो जाता है और लोग कई बार उसे मार डालते हैं। इसके लिए विभाग प्रयास कर रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कैंप लगाएं। साथ ही विभाग के कर्मचारियों को भी ट्रेंकुलाइजेशन की विधि भी समझाई जा रही है।

अगर जंगली जानवर शहर में आता है तो उसको पकड़ने के लिए वन्य प्राणी विंग की स्पेशल टीम होती है, जिन्हें जंगली जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है इसके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है।

पालतू जानवरों का भी होगा बीमा

मैसूर की संस्था नेशनल कंजरवेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर वन विभाग पालतू जानवरों का भी बीमा करेगा। मुख्य अरण्यपाल संजीवा रेड्डी कहते हैं कि लाहुल-स्पीति में इस संस्था ने लोगों से याक का बीमा करवाया है। संस्था के साथ

मिलकर अन्य क्षेत्रों में भी इस स्कीम को चलाया जाएगा। यह संस्था 20 साल से प्रकृति के बारे में लोगों को जागृत कर रही है।

दैनिक जागरण, 8 अप्रैल, 2010

....

Birth of brown bear raises hopes of success

There are only three brown bears, one female and two male, at Kufri kept under the breeding and conservation programme started three years back. A team of the Wildlife Department along with veterinary experts visited the zoo today to ensure that this time all goes well and the cub survives

Birth of a cub at the Himalayan Nature Park at Kufri under the brown bear breeding and conservation programme has raised hopes of the wildlife authorities about the success of the project aimed at conserving one of the most rare and endangered species in captivity.

It was just two days back that staff at the Kufri nature park was pleasantly surprised to see a cub trailing his mother when the duo ventured out of their night shelter for the first time since birth. "The cub appears to be over a month old but it is only now that she stepped out of the night shelter along with the cub, who appears to be healthy and fit." said KS Thakur, conservator (wildlife).

There are only three brown bears, one female and two male, at Kufri kept under the breeding and conservation programme started almost three years back. Though a cub was born earlier also, it could not survive. A team of the Wildlife Department along with veterinary experts visited the zoo today to ensure that this time all goes well and cub survives.

"We are exploring all options to keep the cub safe and for this we are likely to segregate the mother and the cub from the two male bears as there are chances of quarrel as the mother gets aggressive at times," said Thakur. The procedure would have to be carried out very cautiously after tranquilising the animals so that no harm comes to the cub.

Though there is no estimation of the exact number of brown bears in Himachal, their number is not too large. As such it was almost three years ago that the brown bear breeding and conservation programme was launched with Himalayan Nature Park, Kufri, being made the coordinating zoo. The other participating zoos include the ones at Nainital in Uttarakhand and in Jammu and Kashmir.

Brown bear is normally found at a height of above 9,000 feet. Black bear, which is far more common, if found at an altitude lower than this. The funds for the breeding programme of the brown bear are being received from the Central Zoo Authority (CZA) and the state funds. "Though funds are not a problem, once the master plan for Kufri zoo awaiting central approval is cleared, ample amount of money will be received from the CZA," Thakur said.

The Wildlife Institute of India has also been entrusted the task of undertaking a survey to find out the number of brown bears in Himachal.

The Tribune, April 20, 2010

....

कुफरी के काले हिरणों को मिला नया आशियाना

सोरंग हाइड्रो कंपनी दुर्लभ प्राणियों को लेगी गोद इसी माह होगा करार

वाइल्ड लाइफ विंग सालाना कमाएगा 84 हज़ार

नेचर पार्क कुफरी के 'काले हिरणों' को सोरंग हाइड्रो पावर गोद लेने जा रहा है। वन्य प्राणी विंग इस माह के अंतिम सप्ताह कंपनी के साथ करार करेगा। कंपनी द्वारा काले हिरणों के जोड़े को गोद लेने से जहां वन्य प्राणियों को संरक्षक मिलेंगे, वहीं विंग को सालाना 84 हजार की आय होगी। वाइल्ड लाइफ विंग ने सोरंग हाइड्रो पावर को ब्लैक डियर को गोद लेने के लिए संपर्क साधा था। इसके बाद कंपनी ने वन्य प्राणियों को गोद लेने के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने इसके लिए करार से पहले ही 42 हज़ार रुपए जमा भी करवा दिए हैं। करार के बाद हिरणों के आश्रय स्थल पर कंपनी के नाम का बोर्ड लगाया जाएगा। करार की अवधि के दौरान वन्य प्राणियों के खाने-पीने व देख-रेख का खर्चा कंपनी ही वहन करेगी। वन्य प्राणी विंग के अधिकारियों के मुताबिक एचपी पावर कारपोरेशन लिमिटेड, एचपी ट्रांसमिशन कोर्पोरेशन व कुफरी फन वर्ल्ड के साथ भी वन्य प्राणियों को गोद लेने के लिए संपर्क साधा है। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी ने वन्य प्राणियों को गोद लेने में रुचि दिखाई है। जल्द ही इस को लेकर करार किया जाएगा। नेचर पार्क कुफरी स्थित वन्य प्राणियों को गोद देने की योजना को वन्य प्राणी विंग ने कुछ वर्ष पहले शुरू किया था। अंबुजा कंपनी द्वारा पिछले वर्ष पार्क में ब्राउन बियर, थोरल व कक्कड़ प्रजाति के

वन्य प्राणियों को पांच वर्ष के लिए गोद लिया है। वन्य प्राणियों को गोद लेने की एवज में कंपनी ने अढ़ाई लाख रुपए वाइल्ड लाइफ विंग को दिए हैं, जबकि हिमाचल बिजली बोर्ड ने स्ना लैपर्ड की तीन साल के लिए अडॉप्ट किया है। दुर्लभ प्रजाति के इस प्राणी को गोद लेने की एवज में वार्ड एक लाख 80 हज़ार रुपए हर वर्ष विंग को दे रही है। वाइल्ड लाइफ विंग के कंजरवेटर केएस ठाकुर ने बताया कि सोरंग हाइड्रो पावर ने ब्लैक डियर को गोद लेने के लिए रूचि दिखाई है। उन्होनें बताया कि कंपनी ने इसके लिए 42 हजार रूपए की राशि भी चुकता कर दी है। उन्होंने बताया कि इस माह के अंत तक गोद लेने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा।

दिव्य हिमाचल, 22 अप्रैल, 2010

House sparrow vanishing fast

Death Knell experts blame it on indiscriminate use of pesticides, rising number of mobile phone towers

There was a time when mornings used to start with the tuneful chirping of house sparrows, but nowadays it is hard to find them. Their numbers are fast dwindling in Bilaspur and other lower areas of Himachal Pradesh.

"The indiscriminate use of pesticides in agriculture and the increase in the number of mobile phone towers, which emit harmful radiations, are the main reasons behind their declining population," said environmentalist Kulbhushan Upmanyu. He said concrete jungles had encroached upon the natural habitats of house sparrows and many other birds.

"The crops vegetables and fruits on which farmers spray pesticides and insecticides are staple food for these sparrows," said Upmanyu.

"I haven't sighted a house sparrow for ages, though I occasionally come across some wild species os sparrows. There was a time when wee used to feed them grains," said Mena Kumari, a resident of Roura village on the banks of Gobind Sagar lake.

"My entire courtyard used to be full of house sparrows in the morning and evening, but over the years I have noticed a decline in their numbers," said Narindra Joshi, a retired principal who has been living here since the old town was submerged in Gobind Sagar after the construction of Bhakra dam.

District Forest Officer Pushpinder Rana said sparrows were an indicator of a healthy environment and helped in maintaining an ecological balance by feeding on insects. "Lack of food and nesting sites, the increase in the number of mobile towers and rampant use of pesticides are the reasons why these birds are disappearing. We should plant native trees which attract insects and pests, all of which are part of the eco-sytem. We should stop using chemical pesticides in our garden," he suggested.

The DFO said UK researcher Dr. Kate Vincent had found out that the dearth of insects was one of the main reasons behind the declining numbers of house sparrows, which feed exclusively on insects for the first 15 days of their life span.

Hindustan Times, April 26, 2010

Spotting of snow leopards a good sign

The spotting of two snow leopard by wildlife staff near Chichim in Kibber area of Lahaul-Spiti area a few days back has raised the hopes of an increase in the number of the highly endangered animal for which a special conservation programme is being launched.

It was on March 31 that two adult snow leopards were spotted close to Chichim village in Spiti by a team comprising wildlife staff and members of the Nature Conservation Foundation, Mysore, who have been working in the area for some time.

In the past, there was only indirect evidence in the form of pictures captured through the trap cameras or their pug marks which confirmed the presence of the majestic animal in the area.

"The team saw the two snow leopards at about 5-30 pm near Chichim who were in a playful mood and remained in sight for about an hour, raising the hopes of the success of the project," said KS Thakur, conservator (wildlife).

The fact which further confirmed the presence of the animals in the area was their footprints, droppings and the killings of animals in the area, he added.

Though no proper survey has been undertaken to find out the exact number of snow leopard in the state, it is estimated that their strength could be around 12.

The state Wildlife Department has sent a project worth Rs. 60 lakh to the Centre for launching the "Snow Leopard Project" which will be undertaken in a phased manner in Spiti area for conservation of the animal found at great heights in the Himalayan region.

The Mysore-based Nature Conservation Foundation has already been entrusted the task of preparing a management plan for

conservation of the animal. They have installed trap cameras at several places frequented by the animal and on several occasions the pictures of the animal have been captured.

According to wildlife authorities, once the plan was ready, its implementation would start as the actual project would be successful only if suitable and ideal conditions were created for the animal. This includes developing grasslands for herbivores that are essential for serving as prey for the snow leopard.

As such, it is with the help of an integrated approach that efforts are on to somehow bring about an increase in the number of snow leopards in the state.

At present, there is one snow leopard on display at the Himalayan Nature Park at Kufri, which was brought from a Darjeeling zoo.

The Tribune, April 27, 2010

....

वाइल्ड लाइफ संरक्षण को चार डाक्यूमेंटरीज

प्रचार-प्रसार पर 68 लाख खर्च करेगा विंग

दो वर्ष में तैयार होगा प्रोजेक्ट

मुंबई के माइक पांडे बनाएंगे वृत्तचित्र

हिमाचल प्रदेश वन विभाग का वाइल्ड लाइफ विंग पहली बार वाइल्ड लाइफ के संरक्षण व इससे जुड़ी शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 68 लाख खर्च करके चार डाक्यूमेंटरीज तैयार करने जा रहा है। इसका जिमा मुंबई आधारित माइक पांडे को सौंपा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस कार्य के लिए उन्हें 10 लाख रुपए की अदायगी भी कर दी है। दो साल की अवधि में चारों डाक्यूमेंटरीज तैयार कर दी जाएंगी। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े प्रोजैक्ट को किसी निजी पार्टी को सौंपने से पहले वाइल्ड लाइफ विंग ने विभाग के प्रचार विंग को ही विश्वास में नहीं लिया, जबकि महकमे से जुड़े प्रचार कार्यों में इस विंग का खास रोल रहता है। बहरहाल इन चार डाक्यूमेंटरीज़ में पौंग पर आधारित प्रवासी पक्षियों से जुड़ी जानकारी, राज्य पक्षी वेस्ट्रन ट्रैगोपान, हाई अल्टीट्यूड पर स्थित चंद्रताल व अन्य झीलों सहित मौसम बदलाव विषय शामिल रहेंगे। इनका मकसद पश्चिमी हिमाचल की वाइल्ड लाइफ को प्रचारित करना बताया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ विंग के चीफ कंजरवेटर संजीवा पांडे ने इस प्रोजेक्ट की पुष्टि की है। सूत्रों का कहना है कि वाइल्ड लाइफ विंग बड़ा प्रोजेक्ट तो तैयार करने जा रहा है, मगर इसका प्रचार व प्रसार किन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा, इसकी ठीक से जानकारी तक नहीं है। संजीवा पांडे से जब इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि निजी चैनलों से इन डाक्यूमेंटरीज को प्रचारित करवाने का प्रयास किया जाएगा। जाहिर है डाक्यूमेंटरीज तैयार करने से पहले इस बात की भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है कि इनका प्रचार कैसे होगा। जानकारों के मुताबिक निजी चैनल दस मिनट की ही डाक्यूमेटरी चलाने के लिए लाखों की रकम वसूल करते हैं। यहां तक कि डिस्कवरी व नेशनल जियोग्राफिक चैनलों पर भी प्रचार के लिए लाखों की रकम खर्च करती होती है। उनका कहना है कि चूंकि यह प्रदेश में अपनी तरह का पहला प्रयास है। लिहाजा इस बारे मे यदि भावी योजना सार्वजनिक नहीं की गई, तो इस पर सवाल उठ सकते हैं। वह भी ऐसे में जब वाइल्ड लाइफ विंग ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने से पूर्व महकमे के प्रचार विंग को विश्वास में नहीं लिया हो। उधर, संजीवा पांडे का कहना था कि माइक पांडे वाइल्ड लाइफ आधारित फिल्में तैयार करने के माहिर हैं। उन्हें ग्रीन ऑस्कर से भी सम्मानित किया जा चुका है।

दिव्य हिमाचल, 5 मई, 2010

....

चीड़ फिजेंट के संरक्षण को 52 लाख

आखिर अब वह समय नजदीक आ ही गया, जब विलुप्त होती जा रही दुर्लभ प्रजाति के पक्षी चीड़ फिजेट की संख्या को बढ़ावा दिया जाए। इस दुर्लभ प्रजाति के पक्षी चीड़ फिजेंट को संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्रिय पक्षी विहार प्राधिकरण (सीएजैड) द्वारा प्रस्तावित योजना के अंतर्गत 52 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं।

नोडल एजेंसी घोषित चायल में चीड़ फिजेंट को बचाने के लिए योजना के तहत बिजली, पानी के कनेक्शनों, पैन निर्माण का कार्य तथा भवन निर्माण का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इसे अब सिर्फ लांच करवाना शेष है। इसकी पुष्टि वन मंडलाधिकारी वन्य प्राणी नागेश गुलेरिया ने की है। इस पक्षी के जिन जोड़ों पर पहले शोध किया जा चुका है, उनकी अनुवांशिक शक्ति समाप्त होने के कारण कुछ दिनों के भीतर वनों में विचरण कर रहे चीड़ फिजेंट के इन जोड़ो को तैयार किए गए पैन में रखकर अनुसंधान आरंभ कर दिया जाएगा।

यह पक्षी मोनाल के बाद प्रोदशिक घोषित पक्षी वैस्टर्न ड्रेगोपैन के बाद दूसरे स्थान पर आता है। सेंट्रल जू अथॉरिटी द्वारा योजना के लिए स्वीकृत 3. 30 करोड़ रुपए में से 52 लाख रुपए प्राप्त हो चुके हैं, जिसके लिए चीड़ फिजेंट के

जोड़ों में प्रजनन के लिए पैन का निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं भवन निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है।

दिव्य हिमाचल, 5 मई, 2010

वन्य जीव अभ्यारण्यो की परिधि से मुक्त होंगे 775 गांव

वन विभाग ने शुरू की प्रक्रिया

ग्रामीणों को मिलेंगे वन अधिकार तथा होगा क्षेत्र का विकास

प्रदेश में कुल 775 गांव वन्य जीव अभ्यारण्यों की परिधि से मुक्त होंगे। इसके लिए वन विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। वन्य जीव अभ्यारण्यों के क्षेत्र से बाहर होने पर ग्रामीणों को उनके वन अधिकार मिल सकेंगे। साथ ही यहां के रुके हुए विकास को भी गति मिल सकेगी। यह प्रक्रिया शुरू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य होगा। युक्तिकरण के बाद 793 गांवों में से 18 गांव ही रह जाएंगे। हालांकि अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

वन विभाग ने युक्तिकरण के तहत कुछ अभ्यारण्यों का क्षेत्रफल बढ़ाने तथा कुछ को घटाने की योजना बनाई है। ज्ञात हो कि जो गांव वन अभ्यारण्यो के अंतर्गत थे वहां वाइल्ड लाइफ सेंक्च्युरी एक्ट के तहत कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाए हैं। इन गांवों को अभी भी मीलों पैदल चलना पड़ता है क्योंकि यहां सड़कें ही नहीं पहुंची हैं। यहां तक कि लोग जंगलों से लकड़ी भी नहीं उठा सकते, न ही पेड़ काट सकते हैं। वन विभाग ने योजना बनाई है कि इन गांवों को अभ्यारण्य की परिधि से बाहर किया जाए।

उल्लेखनीय है कि युक्तिकरण से वन अभ्यारण्यों का क्षेत्रफल घटेगा नहीं बल्कि 1249 वर्ग किमी और बढ़ जाएगा। वन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार वन्य जीव अभ्यारण्यों की परिधि के अंतर्गत 793 गांव हैं। युक्तिकरण के बाद इन गांवों की संख्या 18 रह जाएगी। अभी वन अभ्यारण्यों का भौगोलिक क्षेत्रफल हिमाचल के कुल भूभाग का 12.8 प्रतिशत है, युक्तिकरण के बाद यह बढ़कर 15.1 प्रतिशत हो जाएगा।

अभी अभ्यारण्यों के अंतर्गत 1. 15 लाख आबादी है, युक्तिकरण के बाद केवल 1700 आबादी रह जाएगी। वन अभ्यारण्यों की युक्तिकरण के बाद 32 वाइल्ड लाइफ सेंक्च्युरी में से केवल 25 रह जाएगी जबकि राष्ट्रीय पार्कों की संख्या में इजाफा हो जाएगा। प्रदेश में इस समय दो राष्ट्रीय पार्क हैं, जो बढ़कर पांच हो जाएंगे। पीसीसीएफ (वाइल्ड लाइफ) एके गुलाटी का कहना है कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के निर्देशों पर ही वन अभ्यारण्यों का युक्तिकरण किया जाएगा। इससे लोगों को काफी फायदा होगा। युक्तिकरण के बाद इन गांवों में विकास संभव हो सकेगा।

दैनिक जागरण, 17 मई, 2010

बंदरों को भगाते 'चुनिया' घायल

लारेंस स्कूल में बंदरो से मुक्ति पाने का नायाब तरीका

लारेंस स्कूल सनावर प्रशासन ने बंदरों के उत्पात व दहशत से बचने का नायाब तरीका ढूंढ निकाला है, जिससे सनावर में बंदरों के काटने के मामलों पर भी पूर्ण विराम लग गया है। लारेंस स्कूल द्वारा अपनाए गए तरीके से खुरापाती बंदरों के आतंक से मुक्ति पाई जा सकती है।

लारेंस स्कूल सनावर प्रशासन ने बंदरों को भगाने के लिए छह लंगूरों को काम पर लगा रखा है। लंगूरों के मालिक को बकायदा इस कार्य का पारिश्रमिक दिया जाता है। शुक्रवार को भी जब सुबह लंगूर स्कूल कैंपस से बंदरों को बाहर भगा रहे थे तो चुनिया नाम की लंगूर पर दर्जनों बंदरों ने हमला कर दिय। चनिया ने बहादुरी से बंदरों का सामना किया व उन्हें कैंपस से बाहर खदेड़ दिया। स्कूली बच्चों को बचाती चुनिया लंगूर घायल हो गई, लेकिन बंदरों को बच्चों के पास फटकने नहीं दिया।

स्कूल के पीआरओ आरएस चौहान ने बताया कि सुबह जब बच्चे खेलकूद व जौगिंग पर निकलते हैं तो बंदरों का डर नहीं रहता है। स्कूल प्रशासन के सराहनीय कार्य पर अभिभावक भी खुश हैं व बच्चो की चिंता से मुक्त हैं। द लारेंस स्कूल सनावर के मुख्याध्यापक प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि पहले स्कूल में बच्चों व अध्यापकों पर बंदर हमला करते थे। कैंपस में आए दिन मंकी बाईट का मामला पेश आता था। कैंपस में बहुत से वानर थे। दिल्ली से किसी अभिभावक ने बताया कि बंदरों के आतंक से लंगूरों के जरिए मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद स्कूल से बंदरों को भगाने का कार्य छह लंगूरों को सौंपा गया। अब मंकी बाईट का कोई मामला नहीं है। लंगूर बच्चों को बचाते हुए स्वयं घायल हो जाते हैं।

दैनिक जागरण, 17 मई, 2010

महिलाएं करेंगी बंदरों का 'इलाज'

बिलासपुर में मुक्तिवाहिनी संगठन का गठन

अब तक सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुके उत्पाती बंदरों को आतंक से हमेशा निजात पाने को बिलासपुर की महिलाएं उठ खड़ी हुई हैं। गुस्साई महिलाओं ने मुक्तिवाहिनी संगठन का गठन कर लिया है, जिसकी कमान अध्यापिका अरूणा शर्मा को सौंपी गई है। यही नहीं बंदर पकड़ने के लिए महिलाएं अपने स्तर पर जाल बनाएंगी। इसके अलावा महिलाओं ने परमिट धारक शूटरों को बंदर भगाने के लिए गोलियों का खर्चा देने का भी निर्णय लिया है। काबिलेगौर रहेगा कि बिलासपुर शहर के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लोग बंदरों के उत्पात से परेशान हैं। अब तक उत्पाती बंदर जिला के सैकड़ों लोगों को अपना निशाना बना चुके हैं। शहर के धौलरा वार्ड में हाल ही में बंदर ने घर के आंगन में काम में जुटी महिला पर अचानक हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बंदरों के खौफ के चलते लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराने लगे हैं। बंदरों को पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग व सरकार से गुहार लगाई, लेकिन इन्हें पकड़ने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बन सकी। वन्य प्राणी विंग की टीम बंदरों को पकड़कर ले जाती है ओर नसबंदी करने के बाद वापस उसी जगल पर छोड़ जाती है। जनता चाहती है कि बंदरों को किसी अन्यत्र स्थान पर छोड़ा जाए। बहरहाल अरूणा शर्मा संगठन की कमान संभालेगी और जरीना, नीलम कुमारी, शांति मोदगिल, सुदर्शना, निक्की देवी, उमा पाल और सुनीता देवी आदि कार्यकारिणी पदाधिकारी नियुक्त की गई है। संगठन का निर्णय है कि महिलाएं अपने स्तर पर जाल बनाएंगी। इसके अलावा जिस शूटर को भी बंदर मारने को परमिशन मिलेगी। उसे गोलियों का खर्चा दिया जाएगा। संगठन की प्रधान अरूणा शार्मा की मानें तो उत्पाती बंदरों ने जीना मुहाल कर दिया है और ये अब आमजन के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। उधर शहर के धौलरा व लखनपुर वार्ड का प्रतिनिधिमण्डल शुक्रवार को उपायुक्त नंदिता गुप्ता से मिला और बंदरों से निजात दिलाने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमण्डल में पार्षद रजनी शर्मा, अरूणा शर्मा, केश पठानिया, एमएल शर्मा, मनमोहन, बजेन्द्र, नीलम, शांति मोदगिल, जरीना, शमीम अख्तर, सुदर्शना, राकेश, निक्की, रणजीत, सुनीता, निर्मला और नरेन्द्र शर्मा आदि शामिल थे। उपायुक्त ने शीघ्र उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।

दिव्य हिमाचल, 5 जून, 2010

E-Coli bacteria thwarts tragopan breeding plan

With almost every bird in the Sarhan pheasantry infected with E-coli bacteria, the Wildlife Department has been forced to thwart breeding of the highly endangered western tragopan for the season. virtually grounding the conservation breeding programme, at least, for now.

The decision was taken after random tests conducted in the wake of death of four precious birds, three of which succumbed to E-coli infection, turned out to be positive, making it evident that the infection was widespread. Since, the bacterial infection flares up during the breeding process. the authorities decided to prevent it by using physiological techniques.

Principal chief conservator of forests, wildlife, AK Gulati informed that method like "shortening the day-light hours" were being used to ensure that the breeding process was retarded. The breeding process is set naturally when the days lengthen in summer as the birds feel more secure from predators and plenty of food is available, he added.

The nine pairs of western tragopan still available in the pheasantry had laid over 65 eggs so far in several clutches but the effort was to ensure that there was no brooding and hatching as of new chicks would be in all likelihood to be infected with the bacteria.

There are 11 males and nine females in the pheasantry and this is the only place in the world having the rare western tragopan in captivity. All birds have been treated for E-coli infection. The topsoil of enclosures has also been replaced.

Gulati said bigger enclosures were being constructed at the pheasantry which would not only create natural environment for the birds but also help in preventing spread of infection.

He said the death of four birds would not affect the conservations breeding programme as only seven pairs were required for the purpose and the pheasantry still had nine pairs.

Sarhan was put on the world pheasant breeding map when the rare western tragopan was bred in captivity for the first time in the world in 2005. The success of the programme would depend on the survival of birds.

Much would depend on whether or not he birds recover from the infection before the onset of next breeding season.

The Tribune, 9 June, 2010

....

स्नो लैपर्ड पर जल्द होगा अनुसंधान

प्रदेश में वाइल्ड लाइफ विंग स्थापित करेगा रिसर्च सेंटर

पूरे विश्व में आकर्षण का केन्द्र बनते आए अति दुर्लभ स्नो-लैपर्ड पर अनुसंधान के लिए हिमाचल वाइल्ड लाइफ विंग एक निजी संस्थान के सहयोग से रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा। यही नहीं स्नो-लैपर्ड की गणना के लिए लाहुल घाटी सहित कुछ अन्य इलाकों में 40 ट्रैक कैमरे भी स्थापित करने की तैयारी है। इनमें से दस कैमरे लाहुल स्पीति के ऐसे दुर्गल इलाकों में स्थापित किए जा चुके हैं, जहां स्नो लैपर्ड के प्राकृतिक घरौदें माने जाते हैं। हिमाचल वाइल्ड लाइफ विंग के प्रधान मुख्य अरण्यपाल एके गुलाटी के मुताबिक इन तमाम गतिविधियों के जरिए स्नो लैपर्ड की हैबिट्स वे हेबिटेट बारे और रोचक जानकारियां हासिल हो सकती है। स्नो लैपर्ड की गणना (सैंसस) प्रदेश में वर्ष 2004 के दौरान की गई थी। उस दौरान इनकी संख्या 35 आंकी गई थी। पूरे विश्व में मंगोलिया में ही अभी तक स्नो लैपर्ड पर विस्तृत अध्ययन हो सका है। यदि हिमाचल इस दिशा में सफल रहता है, तो विश्व में आकर्षण का यह दूसरा बड़ा केन्द्र साबित हो सकता है। वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों के लिए स्नो-लैपर्ड हमेशा से ही आकर्षण का केन्द्र बनता आया है। बावजूद इसके स्नो-लैपर्ड के प्रजनन व प्रदेश में लगातार गिरती इसकी संख्या को लेकर कोई भी गहन अध्ययन किसी भी देश द्वारा नहीं किया जा सका है।

2004 में थे 780 तेंदुए

हिमाचल में वर्ष 2004 की गणना के मुताबिक 780 के करीब तेंदुए पाए गए थे। वाइल्ड लाइफ प्रमुख एके गुलाटी का कहना है कि तेंदुआ शर्मिला वन्य जीव है। लोगों द्वारा उकसाए जाने पर यह हमला बोलता है। इसका अवैध शिकार रूक सके, लिहाजा सरकार कदम उठाने जा रही है।

दिव्य हिमाचल, 16 जून, 2010

....

Green film festival to start at Gaiety from July 2

The best example of climate change in the world can now be seen on the big screen, as the Centre for Media Studies (CMS) hosts a three-day environment and wildlife film festival at Shimla, popularly known as CMS Vatavaran.

As many as 42 award-wining films portraying the festival theme 'Change and Sustainable Technologies' will be screened at Gaiety Theater here from July 2 to 4.

Chief Minister Prem Kumar Dhumal will inaugurate the festival. The first film to be screened is "The Weeping Apple Tree' by Vijay S. Judah. The film showcases the shifting apple-growing belt in Himachal.'

'A fable from the Himalayas', a film by Nitin Das, is another film based in Lahaul and Spiti district of Himachal. The film is a magical tale about a young boy who finds the solution to global warming from a monk in the mountains.

"Films explore varied subject, including danger to shahtoosh, sinking of Maldives, solid waste management in cities, endangered birds, the Shola forests of the Western Ghats and Maiti Andolan of Uttarakhand. The entry will be free," said Narendra Yadav, Manager Communications of CMS, while talking to reporters here.

The Departments of Forests and Environment and Language. Art and Culture and World Wide Fund (WWF) are also assisting the CMS in the festival.

The State Director of the WWF Himachal, Vandana Thaplyal, said the festival would bring on one forum individuals, groups and NGOs working in the field of environment conservation to initiate a debate on future of carbon neutrality in Indian cities.

Principal Chief Conservator of Forest (Wildlife Wing) A.K. Gulati said that on the second day, a special section dedicated to wildlife would be screened. "We will try to show short films on conservation of Western Tragopan being done in Sarahan and Chir Pheasant in Chail in Himachal," said Gulati.

The organisers would invite students of all schools in the capital and periphery areas to watch the films.

A short film workshop on bio-diversity conservation and climate would also be held.

Hindustan Times, 16 June, 2010

....

वाइल्ड लाइफ विंग दिखाएगी कमाल

जजुराना के प्रजनन के लिए विभाग तैयार

वाइल्ड लाइफ विंग सराहन डिविजन में इन दिनों राज्यपक्षी जजुराना के

प्रजनन की तैयारी शुरू हो चुकी है। बुढ़ी हेन के जरिए इस बार फिर वाइल्ड लाइफ विंग में कमाल दिखाने को खासा उत्साह है। वैसे जून माह के आखिरी महीने में जजुराना प्रजनन का कार्य पूरा कर लिया जाता है लेकिन सराहन पक्षी विहार में करीब आधा दर्जन जजुराना पक्षियों में बीमारी फैलने के चलते इस बार प्रजनन में काफी देरी हुई है।

जानकारी अनुसार सराहन पक्षी विहार में जजुराना का क्लच टर्म 21 जून को समाप्त हो चुका है। अब मादा जजुराना के जरिए प्रजनन की तैयारी चल रही है। अब तक पक्षी विहार में करीब 16 से ज्यादा अंडे तैयार किए गए हैं और शीघ्र ही इन अंडों को प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पता चला है कि इस बार ब्रूड़ी हेन के अलावा मादा जजुराना के जरिए प्रजनन की पूरी तैयारी की गई है।

28 दिनों का पीरियड फिक्स

जजुराना का क्लच पीरियड समाप्त होने के बाद ही प्रजनन के प्रोसेस को शुरु किया जाता है। वैसे आम पक्षियों की मानिंद जजुराना पक्षी अंडे नहीं देता और न ही अंडे देने की नियमित प्रक्रिया रहती है। चूंकि राज्य पक्षी जजुराना विश्व में सबसे शर्मिला पक्षी माना जाता है इसलिए इसके प्रजनन व क्लच पीरियड में विभाग को खासी सावधानियां बरतनी पड़ती है। वाइल्ड लाइफ विशेषज्ञों के अनुसार 28 दिनों के भीतर प्रजनन की पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है। और अगर समय ज्यादा बीत जाए तो प्रजनन असफल माना जाता है। प्रजनन के दौरान मादा जजुराना के लिए विशेष किस्म की घास मंगवाई गई है और इस दौरान पक्षी विहार में आने-जाने वाले लोगों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया जाता है। जजुराना प्रजनन के वाइल्ड लाइफ विंग को वर्ष 1996 में पहली बार सफलता मिली। हालांकि इससे पहले भी सराहन पक्षी विहार में प्रजनन की प्रक्रिया चलाई गई जिसमें कुछ हद तक ही सफलता मिली।

वर्ष 1996 के बाद पक्षी विहार में सफल प्रजनन हो रहा है। वाइल्ड लाइफ विंग ने राज्य पक्षी जजुराना की संख्या को बढ़ाने के लिए एक अफसर समेत दो वन कर्मियों को इंग्लैंड में प्रशिक्षण दिया था जिसके चलते अब विंग को जजुराना प्रजनन में खासी सफलता मिल रही है। मौजूदा दौर में राज्य पक्षी जाजुराना की संख्या इतनी कम हो चुकी है कि इन्हें उंगलियों पर आसानी से गिना जा सकता है। अब दुर्लभ प्रजाति के इस पक्षी को बचाने के लिए सराहन में पांच करोड़ रूपए का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट तैयार होने से राज्य पक्षी को बचाया जा सकेगा।

दैनिक भास्कर, 23 जून, 2010

....

कांगड़ा की आबोहवा ने बचा लिए गिद्ध

ब्रीडिंग करने वाले 25 जोड़े पाए गए

पर्यावरण व पक्षी प्रेमियों के लिए खबर राहत भरी है। विलुप्त होने की कगार पर खड़े व्हाइट बीक स्पलींड बील्ड व रेड हेडिड गिद्ध की प्रजातियां हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा वैली की आदर्श आबोहवा में जीवित हैं और अपना वंश बढ़ा रही हैं। भारत, पाकिस्तान व नेपाल में पाई जाने वाली यह प्रजातियां 99 फीसदी तक विलुप्त हो चुकी है जिस पर देश के वैज्ञानिक चिंता जता रहे हैं। प्रदेश विवि के बायोसांइस विभाग के युवा वैज्ञानिक डॉ. एमएल ठाकुर ने हिमाचल में इन गिद्धों के अस्तित्व को खोजने में सफलता पाई है। इन प्रजातियों पर स्टडी करने वाले वैज्ञानिक एमएल ठाकुर की पहले डेढ़ साल की मेहनत में जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक कांगड़ा वैली में इन गिद्धों की आबादी अभी भी मौजूद है।

एमएल ठाकुर के अनुसार कांगड़ा के शाहपुर, नगरोटा सूरियां, नुरपूर में इन प्रजातियों का अस्तित्व बचा है। यहां पर इनके 30 घौंसले मिले हैं। इसके अलावा 25 युवा जोड़े ऐसे हैं, जो ब्रीडिंग करने में सक्षम हैं। प्रदेश की लोअर बेल्ट में दिखे इन गिद्धों के संरक्षण के लिए वन विभाग के मुख्य अरण्यपाल डॉ. संजीवा पांडे व साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक डॉ. पैट्रिक बेनसन भी सेवाएं दे रहे हैं। वैज्ञानिक एमएल ठाकुर के अनुसार यह गिद्ध पर्यावरण को साफ रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इनके लुप्त होने से इसका असर पारिस्थितिक पर पड़ता है। संतुलन बनाए रखने के लिए इनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है।

वैज्ञानिक एमएल ठाकुर का कहना है कि इन गिद्धों की प्रजातियां के विलुप्त होने का मुख्य कारण जानवरों में प्रयोग होने वाली डाइक्लोविन दवाई है। मृत पशु के शरीर में अगर दवाई की मात्रा हो तो इसके खाने के बाद गिद्धों में विसरल गाउट बीमारी पनपती है जिससे यह मरते हैं।

अमर उजाला, 30 जून, 2010

....

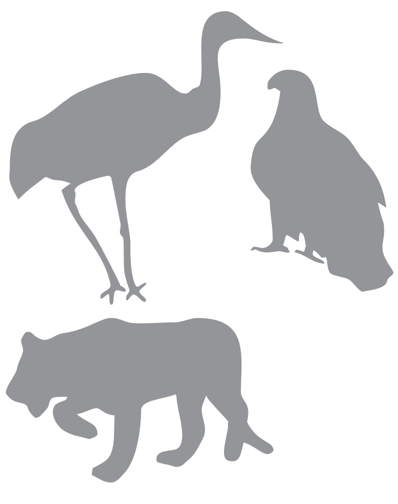

Contact Us

- Principal Chief Conservator of Forests
  Himachal Pradesh Forest Department
  Talland, Shimla
  Tel : 0177-2624207, 2624186, 2623147 & 2624572
  Website : hpforest.nic.in

- Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife)
  Tel : 0177-2624193
  Website: hpforest.nic.in

- Chief Project Director
  Mid Himalayan Watershed Development Project Solan, HP
  Tel : 01792-223043
  Website : hpmidhimalya.org

- Chief Conservator of Forests (Eco-Tourism)
  Tel: 0177-2623036
  Website: www.himachalecotourism.nic.in

- Project Director
  Swan River (Integrated Watershed Management) Project Una, H.P.
  Tel : 01975-225425
  Website : swanriverproject.org

- Director
  Great Himalayan National Park
  Tel: 01902-265320
  Website : greathimalayannationalpark.com

Please feel free to send your feedback to us. In case you would like to add some forestry or wildlife related article in this publication, send the same with details to :

Divisional Forest Officer,
Forest Publicity Division,
Mist Chamber, Khalini, Shimla - 2
email : dfopub-hp@nic.in
Telefax : 0177-2622527